

भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]

No. 11]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7, 2008/वीच 17, 1929

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7, 2008/PAUSA 17, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महाविदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2008

अंतिम जाँच परिणाम

विषय : यूएसए, कोरिया गणराज्य तथा ताईवान के मूल के या वहाँ से निर्यातित फेनोल के आयातों से संबंध में पाटनरोधी जाँच।

सं. 14/5/2006-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. यतः, मैसर्स हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि., मुम्बई तथा मै. एसआई ग्रुप इंडिया लि., मुम्बई (पूर्व में सेनेक्टेडी हरदिलिया लि. के नाम से ज्ञात) (जिन्हें आगे आवेदक कहा गया है) ने अधिनियम और नियमों के अनुसार यूएसए, कोरिया गणराज्य तथा ताईवान (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के या वहाँ से निर्यातित फेनोल (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष संयुक्त रूप से एक आवेदन दायर किया है और संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पाटनरोधी जाँच शुरू करने का अनुरोध किया है।

2. यतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ओर से आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने, जिसे यदि वसूल किया जाता है तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, नियमावली के उप-नियम 5(5) के अनुसार संबद्ध देशों के मूल के या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में पाटनरोधी जाँच शुरुआत करते हुए 11 जनवरी, 2007 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया।

3. और यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 29 अगस्त, 2007 की अधिसूचना सं. 14/5/2006-डीजीएडी के तहत प्रारंभिक जाँच परिणाम अधिसूचित किए और यूएसए, कोरिया गणराज्य तथा ताईवान के मूल के या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की।

क. प्रक्रिया :

4. निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :

(i) दिनांक 11 जनवरी, 2007 को निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने यूएसए, कोरिया गणराज्य तथा ताईवान (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहाँ से निर्यातित फेनोल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना जारी की। पाटनरोधी कार्यवाही में, हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि., मुम्बई तथा मै. एसआई ग्रुप इंडिया लि., मुम्बई (पूर्व में सेनेक्टेडी हरदिलिया लि. के नाम से ज्ञात) (जिन्हें आगे आवेदक कहा गया है) से उक्त उत्पाद के घरेलू उत्पादक के एक बड़े अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हुए घरेलू उद्योग की ओर से प्राप्त आवेदन के बाद शुरू की गई थी। आवेदन में सम्बद्ध देशों के उक्त उत्पादन के पाटन और उससे हुई वास्तविक क्षति का साक्ष्य निहित था, जिसे कार्यवाही की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त माना गया था। प्राधिकारी ने याचिका पर विचार करते समय मै. एसआई ग्रुप इंडिया लि., मुम्बई (पूर्व में सेनेक्टेडी हरदिलिया लि. के नाम से ज्ञात) को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में अलग कर दिया था क्योंकि उन्होंने जाँच अवधि के दौरान पर्याप्त मात्रा में आयात किए थे।

(ii) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जाँच की कार्यवाही शुरू करने से पूर्व आवेदक द्वारा किए गए पूर्णतः प्रलेखित आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में यूएसए, कोरिया गणराज्य और ताईवान के दूतावास को सूचना दी।

(iii) उपर्युक्त नियम 6 के उप नियम (2) के अनुसार प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों, आयातकों, उद्योग एसोसिएशनों, दूतावास तथा आवेदक को उक्त जाँच शुरुआत सम्बन्धी अधिसूचना की प्रति भेजी और उन्हें अपने विचारों से लिखित में अवगत करने का अवसर प्रदान किया।

(iv) उपर्युक्त नियम 6 के उप नियम (3) के अनुसार प्राधिकारी ने आवेदक के अगोपनीय रूपान्तर की एक प्रति सम्बद्ध देशों के सभी ज्ञात निर्यातकों और भारत स्थित यूएसए, कोरिया गणराज्य तथा ताईवान के दूतावासों को उपलब्ध कराई। उपर्युक्त नियम 6 के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत स्थित यूएसए, कोरिया गणराज्य तथा ताईवान के समस्त ज्ञात निर्यातकों और दूतावास को एक प्रति उपलब्ध कराई। उपर्युक्त नियम 6 के अनुसार प्राधिकारी ने भारत स्थित यूएसए, कोरिया गणराज्य तथा ताईवान के समस्त ज्ञात निर्यातकों तथा दूतावास को संगत प्रश्नावली की एक प्रति उपलब्ध कराई। नई दिल्ली स्थित यूएसए, कोरिया गणराज्य तथा ताईवान के दूतावास को भी जाँच शुरुआत सम्बन्धी अधिसूचना के बारे में सूचित किया गया था और उनसे निर्धारित समयावधि के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह देने का अनुरोध किया गया था। निर्यातकों तथा उत्पादकों को भेजे गए पत्र तथा प्रश्नावली की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों के नाम और पते सहित संबंधित दूतावासों को भी भेजी गई थी।

(v) संगत सूचना माँगने के लिए प्राधिकारी ने यूएसए, कोरिया गणराज्य और ताईवान के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियाँ भेजी :

- क) मै. डेकोटा गैसीफिकेशन कंपनी
1600 ईस्ट इंटरस्टेट एवेन्यू
पो. बॉक्स सं. 5540, बिस्मार्क एनडी 58506-5540, यूएसए
- ख) मै. डॉ. कैमिकल कं.
(979) 238-2011
2301 एन ब्रैजोस्पोर्ट बिल्ड
फ्रीपोर्ट, टीएक्स 77541, यूएसए
- ग) मै. जॉर्जिया गल्फ
पैसेडेना
3503, पैसेडेना फ्रीवे
पो. बॉक्स सं. 1959
जिप 77501, पैसेडेना टेक्सास, यूएसए
- घ) मै. शैल कैमिकल्स
डियर पार्क कैमिकल प्लांट एंड रिफाइनरी
5900 हाईवे 225
डियर पार्क टेक्सास, यूएसए
- ड.) मै. फोरमास कैमिकल्स एंड फाइबर कॉर्पोरेशन
फोरमोसा प्लास्टिक्स ग्रुप
201 तुंग ह्वा नॉर्थ रोड
ताईपेई (ताईवान रॉक.)
- च) मै. कुम्हो पी एंड बी कैमिकल्स इंक
319, ह्वाची- दोंग,
येसू सिटी, चोल्ला नाम- डू, कोरिया गणराज्य

(vi) इनमें से किसी भी निर्यातक ने उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में प्रश्नावली का कोई जवाब नहीं दिया है।

(vii) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना माँगते हुए आयातक प्रश्नावली के साथ जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की प्रति निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और भारत में संबद्ध वस्तु के उपयोक्ताओं को भी भेजी गई थी :

- 1) मै. सी.जे. शाह एंड कंपनी
105, बजाज भवन
10वाँ तल, नरीमन प्वाइंट
मुम्बई- 400021
- 2) मै. हरेश कुमार एंड कंपनी
1212, मैकर चैम्बर्स
5 जमनालाल बजाज रोड,
नरीमन प्वाइंट मुम्बई- 400021
- 3) मै. पीसीएल इंडस्ट्रीज
एम-105, कनॉट प्लेस
नई दिल्ली- 110001
- 4) मै. कांतिलाल मणिलाल एंड कंपनी
16, प्रिंसेस स्ट्रीट
मुम्बई- 400003
- 5) सोनकामल इंटरप्राइजेज
10, देव दर्शन अपार्टमेंट
ओल्ड नागरदास रोड अँधेरी (ईस्ट)
मुम्बई-400069
- 6) मै. खेतान ब्रदर्स
सी-17, डालिया इंडस्ट्रियल एरिया
न्यू लिंक रोड के किनारे,
लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट के सामने,
अँधेरी (वेस्ट), मुम्बई- 400058
- 7) मै. शुभम् डाइज एंड कैमिकल्स लि.
1/26, रूप नगर, दिल्ली-110007
- 8) एक्रोन इंटरप्राइजेज
प्लॉट सं. 218-219/3
जीआईडीसी, नरौरा, अहमदाबाद
पिन कोड-382330, गुजरात

- 9) मै. नाइकनावरे कैमिकल्स लि.
1, विद्या भवन, 121, केलुस्कर रोड
शिवाजी पार्क, दादर (वेस्ट)
मुम्बई (महाराष्ट्र)
- 10) मै. पारस डाइज एंड कैमिकल्स
12वाँ तल, विजया बिल्डिंग
17 बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001
- 11) मै. टोरेन्ट फार्मास्यूटिकल लि.
आश्रम रोड,
अहमदाबाद रोड- 380009
गुजरात
- 12) मै. युनाइटेड फॉस्फोरस लि.
ईडिमनी टिरेस, 167
डॉ. एनी बेसेंट रोड
वर्ली, मुम्बई-400018
- 13) मै. रेजिस एंड प्लास्टिक लि.
क्रॉस रोड बी,
मुम्बई-400093
- 14) मै. कैलाश पॉलिमर्स
60, कृष्णा मार्केट,
कालकाजी, नई दिल्ली
- 15) सेंट्रल मेटलिक्स प्रा. लि.
6/221, देवघर रोड,
मतुंगा- 400019
मुम्बई
- 16) मै. वंडर लेमिनाइट्स प्रा. लि.
14, भासा, डायमंड हार्बर रोड,
कोलकाता

- 17) मै. मेघदेव इंटरप्राइजेज
पी. के. हाउस, एच/एम एम.जे. लाइब्रेरी,
एलिसब्रिज, अहमदाबाद
- 18) मै. सतगुरु इंटरनेशनल
204-डी, पॉकेट-12, जसोला विहार,
अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली
- 19) मै. हाई पॉलिमर लेब्स लि.
803, विशाल भवन,
95, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली
- 20) मै. रेनबो कलर्स एंड कैमिकल्स
14/ए, भाविक कॉम्प्लैक्स
घोड़ दोड़ रोड,
सूरत, गुजरात
- 21) मै. ब्लिच मार्केटिंग प्रा. लि.
120, ब्लिच केम कम्पाउंड,
नॉर्थ चंदोला, अहमदाबाद
- 22) मै. कारमेन इंटरनेशनल (प्रा.) लि.
31ए/20, एनपी, सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट
चे, चेन्नई
- 23) मै. कृष्णा एंटीऑक्सिडेंट्स प्रा. लि.
लोप्स मनेर, आई सी कॉलोनी
चंद्रा हो के निकट,
मुम्बई
- 24) मै. एनजीपी इंडस्ट्रिज लि.
एम-13, पुंज हाऊस,
नई दिल्ली
- 25) मै. फार्मसन फार्मास्यूटिकल गुजरात लि.
पाँचवाँ तल, वाणिज्य केंद्र
सयाजीगंज, बड़ोदा

- 26) मै. इंडिया ग्लाइकोल्स लि.
सी-124, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया
फेज-I, नई दिल्ली
- 27) मै. सिंह प्लास्टिसाइजर्स एंड रेजिन्स (आई) प्रा.
बी-316, तीसरा तल
सोमदत्त चैम्बर-1
भिका, नई दिल्ली
- 28) मै. नेशनल प्लाईवुड इंडस्ट्रिज लि.
5, फैंसी लेन, 700001
कोलकाता

(viii) उपर्युक्त अधिसूचना के प्रत्युत्तर में मै. सेंचुरी प्लाई लि. (सम्बद्ध उत्पाद के प्रयोक्ताओं में से एक) को छोड़कर किसी भी आयातक ने निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया। इन जाँच परिणामों पर प्रभाव डालने की दृष्टि से निविष्टियों को ध्यान में रखने के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत सूचना विश्वसनीय नहीं है। अर्थात् अनुबंध 2 में सम्बद्ध वस्तु की प्रति मी. टन दर निकाली गई है जो 22.47 रु. प्रति मी. टन बनती है। अतः इस जाँच के प्रयोजनार्थ इस प्रश्नावली के उत्तर में निहित किसी भी सूचना पर विचार नहीं किया गया है। लैमिनेट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने मौखिक सुनवाई के बाद पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किए थे। मै. सेंचुरी प्लाई के अलावा लैमिनेट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के एक भाग ने भी पाटनरोधी शुल्क का विरोध करते हुए मौखिक सुनवाई के बाद तर्क प्रस्तुत किए थे। प्रसंगवश सेंचुरी प्लाई का एक प्रतिनिधि भी लैमिनेट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से मौखिक सुनवाई में उपस्थित हुआ था जिसका अन्य बातों के साथ-साथ यह तात्पर्य निकलता है कि सेंचुरी प्लाई ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था। तथापि, इनमें से किसी भी पार्टी ने प्राधिकारी को संभार तंत्र/आंकड़ों के रूप में ऐसी कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है जिससे प्राधिकारी को पाटन अथवा क्षति मार्जिन, याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए अंतर का निर्धारण करने अथवा उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अंतर को तय करने के लिए आधार उपलब्ध हो सके। इसके बजाय, उन्होंने केवल अपनी आपत्तियाँ दायर की हैं जिन पर उस सीमा तक विचार किया गया है जिस सीमा तक उन्हें इस जाँच के प्रयोजनार्थ संगत पाया गया है।

(ix) प्राधिकारी ने 29 अगस्त, 2007 की अधिसूचना सं. 14/5/2006-डीजीएडी के तहत प्रारंभिक जाँच परिणाम अधिसूचित किए और हितबद्ध पार्टियों से अनुरोध किया कि वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से लिखित में अवगत कराएँ।

(x) केन्द्र सरकार ने 19.9.2007 की अधिसूचना सं. 105/2007 के तहत अंतिम शुल्क लगाया।

(xi) प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों की मौखिक सुनवाई करने के लिए 9 अक्टूबर, 2007 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जिसमें हितबद्ध पार्टियों ने भाग लिया था। सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाली पार्टियों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का निवेदन किया गया था। प्राधिकारी ने इस जाँच परिणाम में हितबद्ध पार्टियों से प्राप्त लिखित अनुरोधों पर विचार किया है। पार्टियों से अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा व्यक्त विचारों पर प्रत्युत्तर संबंधी अनुरोध दायर करने के लिए भी कहा गया था।

(xii) प्रारंभिक जाँच परिणाम अधिसूचित करने से पूर्व किसी अन्य हितबद्ध पार्टी (घरेलू उद्योग को छोड़कर) द्वारा कोई तर्क या अनुरोध नहीं किया गया है। तथापि, प्रारंभिक जाँच परिणाम के बाद विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए और प्रस्तुत किए गए तर्कों पर इस जाँच परिणाम में कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, वर्तमान प्रकटन विवरण पर हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों पर इस जाँच परिणामों में विधिवत कार्यवाही की गई है।

(xiii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतरण को प्राधिकारी द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा और उसे हितबद्ध पार्टियों के निरीक्षण हेतु खुला रखा।

(xiv) *** यह चिह्न इस अधिसूचना में हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने उसे नियमानुसार गोपनीय ही माना है।

(xv) उपरोक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन जाँच परिणामों के लिए विचारित आवश्यक तथ्यों/ आधार को 3 दिसम्बर, 2007 को ज्ञात हितबद्ध पार्टियों के समक्ष प्रकटित किया गया है और उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर वर्तमान अंतिम जाँच परिणामों में विचार किया गया है।

(xvi) पाटन जाँच में 1 जुलाई, 2005 से 30 जून, 2006 (जिसे जाँच अवधि भी कहा गया है) की अवधि शामिल है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में रुझानों की जाँच हेतु 1 अप्रैल, 2003 से जाँच अवधि की समाप्ति तक की अवधि (जिसे क्षति अवधि भी कहा गया है) को शामिल किया गया है।

(xvii) प्राधिकारी ने मौके पर जाँच की और घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त समस्त सूचना का सत्यापन किया। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार उत्पादन लागत और भारत में उक्त सम्बद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत को निकालने के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत का भी विश्लेषण किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

(xviii) पिछले तीन वर्षों और जाँच अवधि के लिए सम्बद्ध वस्तु के आयातों के व्यौरों की व्यवस्था करने के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से अनुरोध किया गया था।

(xix) जहाँ कहीं किसी हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने अथवा वर्तमान जाँच के दौरान आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने से मना किया है अथवा जाँच में पर्याप्त बाधा उत्पन्न की है, वहाँ प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जाँच परिणाम दर्ज करेंगे।

(xx) प्राधिकारी ने सम्स्त हितबद्ध पार्टियों की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत से संबंधित आँकड़ों पर गोपनीय रूप में विचार किया है क्योंकि इससे उनके प्रतिस्पर्धियों को प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा। अन्य सूचना को तब तक गोपनीय नहीं माना गया है जब तक कि प्रतिवादी पार्टी ने उक्त सूचना को गोपनीय रखने के बारे में पर्याप्त औचित्य प्रस्तुत नहीं किया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तुएँ

ख.1 घरेलू उद्योग के विचार

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के सम्बन्ध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं :

(i) फेनॉल सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 27 और अध्याय 29 के अंतर्गत क्रमशः उपशीर्ष 28071110, 27079900 के तहत वर्गीकृत एक कार्बनिक रसायन है। घरेलू उद्योग ने यह अनुसंधान किया है कि दोनों वर्गीकरणों पर शुल्क की सिफारिश की जानी चाहिए।

(ii) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और यूएसए, कोरिया गणराज्य तथा ताईवान से आयातित फेनॉल समान वस्तु है।

(iii) फेनॉल एक मूलभूत कार्बनिक रसायन है जिसका विपणन दो ग्रेडों अर्थात् क्रिस्टेलिन और हाइड्रेटेड में किया जाता है। दोनों ही ग्रेड फेनॉल के प्रवाह संबंधी विशेषताओं के आधार पर अलग-अलग हैं। इसका विपणन दो रूपों- खुले/बल्क तथा डिब्बाबंद रूप में किया जाता है।

(iv) भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित फेनॉल में कोई अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित फेनॉल भौतिक तथा रासायनिक विशेषताओं जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय है।

(v) फेनॉल का उपयोग फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, लेमिनेट्स, प्लाइवुड, पार्टिकल बोर्ड, बिस्फेनोल-ए, अल्काइल फेनॉल, भेषज, डाइफिनाइल ऑक्साइड आदि के विनिर्माण में किया जाता है।

(vi) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित फेनॉल में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित फेनॉल भौतिक तथा रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी (जिसका विश्व भर के अधिकांश उत्पादकों द्वारा प्रयोग

किया जाता है), कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय है। दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों उत्पादों का उपयोग अदल-बदलकर किया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित फेनॉल समान वस्तु है।

ख.2. आयातकों, उपभोक्तों, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में किसी भी आयातक, उपभोक्ता, निर्यातक तथा अन्य हितबद्ध पार्टी ने कोई टिप्पणी अथवा अनुरोध दायर नहीं किया है।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

7. विचाराधीन उत्पाद यूएसए, कोरिया गणराज्य और ताईवान के मूल का या वहाँ से निर्यातित फेनॉल है। फेनॉल सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत सामान्यतः वर्गीकृत एक मूल कार्बनिक रसायन है। उत्पाद का विपणन दो रूपों- बल्क और डिब्बाबंद रूप में किया जाता है। बल्क बिक्री सामान्यतः खुले रूप में की जाती है जबकि डिब्बाबंद परेषण अत्यंत छोटे कंटेनर भारों और सामान्यतः ड्रमों में डिब्बाबंद रूप में किया जा सकता है। फेनॉल का उपयोग फेनॉल फॉर्मलिहाइड रेजिन, लेमिनेट, प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, बिस्फेनोल-ए, अल्काइल फेनॉल, मेषज, डाइफिनाइलऑक्साइड आदि में किया जाता है। यह उत्पाद भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष सं. 2907.11 और 2707.99 के अंतर्गत वर्गीकृत है तथापि, सीमाशुल्क और आईटीसी एचएस वर्गीकरण, केवल सांकेतिक हैं और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं हैं।

8. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में यह विनिर्दिष्ट है कि समान वस्तुओं का तात्पर्य एक ऐसी वस्तु से है जो विचाराधीन उत्पाद से हर प्रकार से समनुरूप और समान वस्तु है अथवा ऐसी किसी वस्तु के अभाव में ऐसी अन्य वस्तु से है जिसकी विशेषताएँ जाँचाधीन वस्तुओं की विशेषताओं से अत्यंत मिलती-जुलती हैं।

9. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सम्बद्ध देशों के मूल की या वहाँ से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु है। इस मुद्दे पर किसी अन्य हितबद्ध पार्टी ने घरेलू उद्योग के इस दावे पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और सम्बद्ध देशों से आयातित फेनॉल नियमों के अर्थ के भीतर समान वस्तु है।

ग. घरेलू उद्योग एवं आधार

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

10. घरेलू उद्योग के आधार के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

(i) यह याचिका में हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स लि. तथा एसआई ग्रुप (पूर्व में सेनेक्टेडी हरदिलिया लि. के नाम से ज्ञात) द्वारा संयुक्त रूप से दाखर की गई थी। भारत में ऐसी तीन कंपनियाँ हैं जिन्होंने फेनॉल के उत्पादन की क्षमता सृजित की है अर्थात् हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स लि., एसआई ग्रुप (पूर्व में सेनेक्टेडी हरदिलिया लि. के नाम से ज्ञात) तथा नेवेल लिगनाइट। तथापि, नेवेली लिगनाइट ने कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन वर्षों में फेनॉल का कोई उत्पादन/बिक्री नहीं की है। अतः याचिकाकर्ता नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग हैं।

(ii) याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता को नियमों के अर्थ के भीतर “घरेलू उद्योग” माना जाना चाहिए।

ग.2. निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य, ताईवान अथवा यूएसए में सम्बद्ध वस्तु के किसी भी उत्पादक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को कोई उत्तर नहीं दिया है। तथापि, सम्बद्ध वस्तु के प्रयोक्ताओं में से एक प्रयोक्ता मै. सेंचुरी प्लाई लि. ने निम्नानुसार कुछ आपत्तियाँ उठाई हैं :

ग.2.1 सेंचुरी प्लाई लि.

12. प्राधिकारी के लिए एसआई हरदिलिया के कार्य निष्पादन की जाँच अपेक्षित है।

13. एसआई हरदिलिया ने भी सम्बद्ध वस्तु का आयात किया है और प्राधिकारी ने प्रारम्भिक जाँच परिणामों की सिफारिश करते समय माँग-आपूर्ति के भारी अंतर की अनदेखी की है।

14. एचओसीएल की तुलना में एसआई हरदिलिया की उत्पादन लागत कम है।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

15. प्राधिकारी ने इस सम्बन्ध में इस प्रयोक्ता द्वारा दी गई दलील और रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य की जाँच की है। घरेलू उद्योग के आधार के बारे में नियम 2(ख) में निम्नानुसार उल्लेख है :

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न समूचे घरेलू उत्पादकों या ऐसे उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख भाग बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का एक भाग नहीं माना जाएगा।

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक याचिकाकर्ता एसआई ग्रुप (पूर्व में सेनेक्टेडी हरदिलिया लि. के रूप में ज्ञात) ने सम्बद्ध देशों से जाँच अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तु का आयात किया है। यह नोट किया जाता है कि कम्पनी द्वारा किए गए आयात शुल्क मुक्त श्रेणी और शुल्क प्रदत्त श्रेणी के रूप में हैं जिनकी मात्रा अत्यधिक है। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के दायरे से एसआई ग्रुप को बाहर रखना उचित समझा है।

17. याचिकाकर्ताओं को यह निर्देश दिया गया था कि वे एसआई ग्रुप को बाहर करने के बाद क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध कराएँ जो उन्होंने प्रस्तुत कर दी थी। यह सूचना जाँच में भागीदार अन्य हितबद्ध पार्टियों को भी भेजी गई थी और उन्हें क्षति संबंधी सूचना पर अपनी टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।

18. भारत में तीन ऐसी कंपनियाँ हैं जिनके पास फेनॉल के उत्पादन की क्षमता है अर्थात् हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि., एसआई ग्रुप (पूर्व में सेनेक्टेडी हरदिलिया लि. के रूप में ज्ञात) और नेवेली लिग्नाइट। तथापि, नेवेली लिग्नाइट की वार्षिक रिपोर्टों से यह देखा गया था कि इस कंपनी ने जाँच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं किया है। प्राधिकारी ने उपर्युक्त पैरा 16 और 17 में किए गए उल्लेख के अनुसार घरेलू उद्योग के दायरे से एसआई ग्रुप को अलग रखना उचित समझा है। अतः मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. का भारतीय उत्पादन में एक प्रमुख हिस्सा बनता है और वह नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

19. एसआई ग्रुप द्वारा किए गए आयातों के बारे में तर्क दिया गया है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एक आयातक होने के नाते एसआई ग्रुप की सत्यता घरेलू उद्योग के क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए संगत है। जहाँ याचिकाकर्ताओं ने एसआई ग्रुप को घरेलू उद्योग के क्षेत्र में शामिल करने का तर्क दिया है वहीं इन हितबद्ध पार्टियों ने यह तर्क नहीं दिया है कि एसआई ग्रुप को घरेलू उद्योग के दायरे में लाया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने एसआई ग्रुप को घरेलू उद्योग के दायरे से पहले ही अलग कर दिया है।

घ. अन्य मुद्दे

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

20. उत्पाद की प्रकृति और उत्पादन हेतु निविष्टि में अस्थिरता की वजह से शुल्क का बेंचमार्क स्वरूप शुल्क का उचित स्वरूप नहीं है।

21. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एक विशेष मामले के रूप में लेमिनेट्स एसोसिएशन और उसके सदस्यों को निर्दिष्ट प्राधिकारी को संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए दो सप्ताह का समय प्रदान किया था। तथापि, न तो एसोसिएशन ने और न ही लेमिनेट विनिर्माताओं ने कोई सूचना उपलब्ध कराई है। केवल इसी वजह से उनकी आपत्ति अस्वीकार की जानी चाहिए।

घ.2 निर्यातक, आयातकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य, ताईवान या यूएसए में संबद्ध वस्तु के किसी भी उत्पादक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है।

घ.2.1 सेंचुरी प्लाई-लि. तथा लेमिनेट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन

23. घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए अपनी याचिका में संयंत्र की “ दीर्घावधि ” तालाबन्दी के बारे में किसी सूचना का खुलासा नहीं किया है। प्राधिकारी ने जाँच की शुरुआत से पूर्व तालाबन्दी के प्रभाव की जाँच नहीं की है। प्रारंभिक जाँच परिणामों में भी तालाबन्दी की सही अवधि का खुलासा भी नहीं किया गया है। वर्ष 2004-05 के लिए उत्पादन बन्द होने से पूर्व घरेलू उद्योग के निष्पादन में सम्बद्ध देशों से आयातों के बावजूद उल्लेखनीय परिणाम प्रदर्शित हुए हैं।

24. माँग और आपूर्ति में भारी अंतर के बावजूद घरेलू उद्योग द्वारा सम्बद्ध वस्तु का निर्यात किया जा रहा है और घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात तथा प्रयोक्ता उद्योग पर उसके प्रभाव का प्रारंभिक जाँच परिणामों में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

25. घरेलू उद्योग ने किसी प्रकार के विरोध से बचने के लिए भारत में फेनॉल के प्रमुख प्रयोक्ताओं के नामों का खुलासा जान-बूझकर नहीं किया।

26. एसआई ग्रुप द्वारा किए गए आयातों के बारे में सूचना प्रकटित नहीं की गई है। याचिकाकर्ताओं ने इन सभी मुद्दों पर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

27. ऐसा प्रतीत होता है कि दायर की गई याचिका की जाँच नहीं की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जाँच शुरुआत औचित्यपूर्ण है।

28. दायर याचिका पूर्ण नहीं है क्योंकि आवेदन तथा प्रपत्र के भागों का पूर्णतः उत्तर नहीं दिया गया है और न ही आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है।

29. घरेलू उद्योग के मामले को जाँच अवधि से पूर्व बीआईएफआर को भेजा गया है। जैसा कि अधिकारी जानते ही होंगे कि बीआईएफआर को मामला भेजने का कारण वस्तुतः यह है कि निधियों में पूर्णतः कमी आ गई है अर्थात् संचित घाटा शेयरधारकों की निधियों से अधिक हो गया है। हमारा मानना है कि घरेलू उद्योग एसआईसीए के उपबंधों के अनुसार मामला सं. 501/2005 के तहत बीआईएफआर द्वारा एक रूग्ण औद्योगिक कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। प्राधिकारी कृपया बोर्ड द्वारा पारित आदेश सहित बीआईएफआर के मामले से संबंधित समस्त दस्तावेज/अनुरोध माँगे। इस सम्बन्ध में एचओसीएल की 2004-05 की वार्षिक रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके संगत उद्धरण निम्नानुसार हैं :

“ आपकी कम्पनी को वित्त वर्ष 1997-98 से 2003-04 तक घाटा हो रहा था और इसे वित्त वर्ष 2003-04 के अन्त में निवल मूल्य में कमी के बाद एक रूग्ण इकाई के रूप में बीआईएफआर को भेज दिया गया था। ”

30. इस तथ्य से कि कम्पनी का मामला बीआईएफआर को भेज दिया गया है यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कम्पनी का खराब निष्पादन उनकी अंतर्निहित कठिनाइयों के कारण रहा है जिसे सरकार की अनेक रिपोर्टों में स्वीकार किया गया है। यह भी नोट करना महत्वपूर्ण है कि बीआईएफआर हेतु आवेदन भी फेनॉल पर पाटनरोधी आवेदन किए जाने से पूर्व किया गया था। इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट हो जाता है कि ये समस्याएँ सम्बद्ध देशों से आरोपित पाटन के कारण उत्पन्न नहीं हो सकती हैं।

31. याचिका कई मामले में त्रुटिपूर्ण है। प्राधिकारी द्वारा साक्ष्य की पर्याप्तता और सत्यता की जाँच नहीं की गई है। प्राधिकारी को ऐसी त्रुटिपूर्ण याचिका के आधार पर जाँच शुरू नहीं करनी चाहिए थी।

32. याचिका में उल्लिखित क्षति संबंधी सूचना प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचना के अनुरूप नहीं है। याचिका में एक और पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े दिए जाने चाहिए थे।

33. प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी करने का कोई औचित्य नहीं था।

34. प्राधिकारी ने क्षति रहित कीमत के निर्धारण और क्षति मार्जिन की गणना अपनाई गई कार्यप्रणाली का खुलासा नहीं किया है।

35. किसी खास कारण के बिना मै. एचओसीएल संयंत्र को अचानक बन्द करना और इस प्रकार कुल भारतीय क्षमता के ढाई गुने तक माँग/आपूर्ति में भारी अंतर उत्पन्न करना (माँग 152415 मी. टन की है जबकि घरेलू उद्योग की क्षमता केवल 40,000 मी. टन की है)। घरेलू उद्योग देश में माँग की पूर्ति नहीं कर सकता।

36. कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता को तालाबन्दी के एक कारण के रूप में दावा करना मात्र दिखावा है और वर्तमान याचिका के समर्थक एसआई हरदिलिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नियमित रूप से कच्ची सामग्री प्राप्त की जा रही है और उसे कच्ची सामग्री की उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई अड़चन नहीं हुई है।

37. घरेलू उद्योग ने आयात में अनुमानित वृद्धि तथा उत्पादन में गिरावट दर्शाने के लिए जुलाई, 05 से जून, 06 को जाँच अवधि के रूप में जान-बूझकर चुना है ताकि उसे आयात के कारण क्षति के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। जाँच की गलत अवधि का चुनाव किया गया है।

38. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका समूचे प्रयोक्ता उद्योग जो कि भारत में न केवल फेनॉल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है अपितु उसे उन घरेलू उत्पादकों, जो उन्हें दिए गए ऑर्डर के बाद अपेक्षित मात्रा में आपूर्ति से मना करते हैं, के खराब व्यवहार का भी सामना करना होता है, के व्यय पर अपने खुद के निजी लाभ हेतु घरेलू बाजार में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न करने के लिए याचिकाकर्ता कम्पनी के खुद के उद्देश्यों हेतु कानूनी और विधिक व्यापार उपचार उपायों की प्रक्रिया के दुरुपयोग का ज्वलंत उदाहरण है।

39. प्राधिकारी को ऐसे प्रत्येक देश के लिए अलग-अलग कीमत कटौती का खुलासा करना चाहिए।

40. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जाँच परिणामों में पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आयातों के पहुँच मूल्य का खुलासा नहीं किया है ताकि पूर्ववर्ती वर्षों के कीमत रुझानों की तुलना की जा सके।

41. प्राधिकारी ने उपभोक्ता उद्योग के हितों की अनदेखी करने में त्रुटि की है और पाटनरोधी नियम के नियम 6(5) का पालन नहीं किया गया है क्योंकि औद्योगिक प्रयोक्ताओं द्वारा अपनी दयनीय स्थिति के बारे में प्रस्तुत तर्कों पर प्रारंभिक जाँच परिणामों में विचार नहीं किया गया है।

42. यह जाँच पाटनरोधी नियम के नियम 14 के अनुसार समाप्त कर दी जानी चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है जिनका मामला और क्षति के वर्तमान स्तर पर प्रभाव पड़ता है।

घ.2.2 प्राधिकारी द्वारा जाँच

43. घरेलू उद्योग के संयंत्र की दीर्घावधि तालाबन्दी के बारे में सूचना 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकटित की गई है जिसे हितबद्ध पार्टियों को निरीक्षण एवं टिप्पणी हेतु उपलब्ध कराया गया था।

44. जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निर्यात की मात्रा नगण्य रही है। अतः निर्यातों से घरेलू उद्योग का समग्र निष्पादन प्रभावित नहीं हो सकता है।

45. जाँच शुरूआत की सूचना राजपत्र में जारी की गई थी और यह आशा की गई थी कि सभी पक्षकार इससे अवगत होंगे। इसके अलावा, इसकी एक प्रति एसोचैम, फिक्की, सीआईआई सहित प्रमुख व्यापार एसोसिएशनों तथा एक्साइज लॉ टाइम्स जैसे प्रकाशन गृहों को भी भेजी गई थी।

46. एसआई द्वारा आयात-प्राधिकारी ने एसआई को घरेलू उद्योग के दायरे से अलग कर दिया है और इसलिए एसआई द्वारा आयातों के बारे में कोई भी तर्क संगत नहीं है।

47. हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जाँच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के सम्बन्ध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहाँ कहीं आवश्यक समझा है, गोपनीयता प्रदान कर दी है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है और इसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पार्टियों को नहीं किया गया है। जहाँ कहीं संभव हुआ है गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाली पार्टियों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।

48. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना में जाँच शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य प्रदर्शित किया गया था। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने यूएसए, कोरिया गणराज्य तथा ताईवान के मूल की या वहाँ से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों के बारे में पाटनरोधी जाँच शुरू करते हुए 11 जनवरी, 2007 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

49. घरेलू उद्योग द्वारा दायर सूचना की जाँच नियम 5 के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुसार की गई थी और जाँच याचिका में निहित साक्ष्य की पर्याप्तता और सत्यता के सम्बन्ध में संतुष्ट होने के बाद ही शुरू की गई थी।

50. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थिति की भली-भाँति जानकारी है और कम्पनी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं छिपाई गई है। प्राधिकारी द्वारा एसिटोन से संबंधित जाँच के दौरान भी इस मुद्दे की पूर्व में जाँच की गई है जिसमें प्राधिकारी ने निम्नानुसार नोट किया है-

“प्राधिकारी ने बीआईएफआर के तहत एचओसीएल के मुद्दे की जाँच की है और यह नोट किया है कि बीआईएफआर के समक्ष आवेदक द्वारा उल्लिखित कारण यह है कि “कम्पनी की कोचि

इकाई, जो वस्तुतः लाभ कमा रही है, में बिक्री में विदेशी विनिर्माताओं द्वारा उत्पादों के पाटन, जिससे मार्जिन में भारी कमी आई और परिणामतः घाटा हुआ, के कारण 2001-02 में कमी आई। प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि कम्पनी की कोच्ची इकाई जो मूलतः फेनॉल और एसिटोन का विनिर्माण करती है, 2002-06 के दौरान लाभ कमा रही थी लेकिन इस लाभ में 2005-06 के दौरान भारी कमी आ गई थी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कम्पनी की रासायनी इकाई ने 2000-06 के दौरान घाटा उठाया था। अतः प्राधिकारी का यह मानना है कि इकाई को एसआईसीए के अंतर्गत केवल पंजीकृत किए जाने से ही वह पाटनरोधी जाँच के तहत खासकर तब कम्पनी की संगत इकाई अन्य किसी कारण से घाटा नहीं उठा रही थी, राहत की माँग करने के लिए अपात्र नहीं बन जाएगी।”

51. व्यापार सूचना में जाँच की पाटन अवधि तथा पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए क्षति सम्बन्धी सूचना अपेक्षित होती है। इस अवधि के लिए सूचना याचिका में निहित थी और उस पर क्षति निर्धारण हेतु विचार, जाँच और भरोसा किया गया है।

52. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जाँच परिणामों की जरूरत के बारे में संतुष्ट होने के बाद इन्हें जारी किया है।

53. प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत तथा क्षति मार्जिन के निर्धारण के संबंध में सुसंगत प्रक्रिया का पालन किया है। क्षतिरहित कीमत निर्धारण हेतु अपनाई गई कार्यप्रणाली का खुलासा प्रकटन विवरण में अलग से किया जा रहा है। क्षति मार्जिन का निर्धारण आयातों की क्षतिरहित कीमत एवं पहुँच मूल्य के बीच अंतर के रूप में किया गया है।

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन देश में आयातों को रोकना नहीं होता है अपितु पाटित कीमतों पर आयात को सीमित करना होता है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से देश में उत्पाद की उपलब्धता सीमित नहीं होगी।

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि तालाबन्दी के कारण का उल्लेख कम्पनी की 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है। केवल इस वजह से कि इस अवधि के दौरान अन्य भारतीय उत्पादकों को कच्ची सामग्री की कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई, यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि एचओसीएल (घरेलू उद्योग) को ऐसी कठिनाई नहीं हो सकती है।

56. प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जाँच अवधि के नियतन से वर्ष 2005-06 में एचओसीएल की तालाबन्दी के कारण वर्तमान जाँच में किसी प्रकार का विपथन हुआ है। इस आशय के ब्यौरे प्रारंभिक जाँच परिणामों के पैरा 31 में पहले ही स्पष्ट किए जा चुके हैं। वस्तुतः जाँच अवधि के दौरान प्रतिकूल बाजारी स्थितियों को छोड़कर ऐसा कोई आंतरिक कारक नहीं था जिसने पूर्ण क्षमता पर संयंत्र के प्रचालन में बाधा के रूप में काम किया हो।

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले उत्पाद के पाटन के विरुद्ध है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण अन्य बातों के साथ-साथ जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ पर विचार करते हुए किया जाता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रभाव से घरेलू उद्योग को असामान्य लाभ अर्जित करने, खासकर तब जबकि भारत में “कमतर शुल्क नियम” का अनुपालन किया जा रहा है जिसके तहत पाटनरोधी शुल्क की मात्रा क्षति मार्जिन तक सीमित की जाती है, की अनुमति देना है।

58. हितबद्ध पार्टियों द्वारा की गई माँग के अनुसार प्रकटन विवरण में प्रत्येक देश के लिए कीमत कटौती का अलग-अलग निर्धारण किया गया है। इसके अलावा, आयातों के पहुँच मूल्य की उचित गणना भी की गई है और उसका प्रकटन किया गया है।

59. प्राधिकारी ने नियम 6(5) के अंतर्गत अपेक्षानुसार हितबद्ध पार्टियों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया है। वस्तुस्थिति यह है कि ये पार्टियाँ पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के विरोध में तर्कों को छोड़कर कोई सूचना उपलब्ध कराने में विफल रही हैं।

ड. आयात की न्यूनतम मात्रा

60. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्ड एस) से प्राधिकारी को प्राप्त आयात संबंधी आँकड़ों के अनुसार सम्बद्ध देशों में से प्रत्येक देश से सम्बद्ध वस्तु के आयात न्यूनतम स्तर से अधिक रहे हैं।

घ. पाटन मार्जिन का निर्धारण

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 6.8 में यह उपबंध है कि ऐसे मामले में जहाँ कोई हितबद्ध पार्टी उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या जाँच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी उसके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

62. अनुबंध II के पैराग्राफ 1 के साथ पठित करार के अनुच्छेद 6.8 में यह उपबंध है कि जाँच की शुरुआत के बाद यथासंभव शीघ्र जाँच प्राधिकारियों को किसी हितबद्ध पार्टी से अपेक्षित सूचना और जिस ढंग से उक्त सूचना उक्त हितबद्ध पार्टी द्वारा अपने उत्तर में प्रदान की जानी चाहिए, उस ढंग को विस्तार से स्पष्ट करना चाहिए। प्राधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त पार्टी इस बात से वाकिफ है कि यदि सूचना उचित समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है तो प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा जाँच की शुरुआत हेतु आवेदन में निहित तथ्यों सहित उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सम्बद्ध देशों के निर्यातकों और सरकारों को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से सूचना प्रस्तुत करने की जरूरत के बारे में यथोचित ढंग से सूचित किया गया है और पार्टियों को इस संबंध में अपने अनुरोध करने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था। अतः सम्बद्ध देश से सहयोग के अभाव में प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सम्बद्ध देश के संबंध में पाटन मार्जिनों का निर्धारण किया है।

छ. सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत

छ.1 कोरिया गणराज्य

छ.1.1 कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

64. किसी भी निर्यातक ने जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है और कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। किसी आँकड़े के अभाव में प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु पाटनरोधी नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है। उपलब्ध तथ्यों के

आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया गया है। सामान्य मूल्य के परिकलन हेतु बेंजीन की कीमत डीजीसीआईएस के आँकड़ों से और प्रोपीलीन की कीमत आईसीआईएस एलओआर एशिया से ली गई है। घरेलू उद्योग की खपत संबंधी मानकों और मानक निविष्टि-उत्पादन मानदण्डों (एसआईओएन) पर भरोसा किया गया है। उपयोगिताओं के लिए विद्युत को छोड़कर खपत संबंधी मानदण्डों तथा घरेलू उद्योग की कीमत को लिया गया है। विद्युत के लिए दर निर्यातक देश में विद्युत दर की उपलब्ध सूचना के आधार पर ली गई है। परिवर्तन लागत जिसमें श्रम, मूल्य ह्रास तथा विनिर्माण व्यय शामिल हैं, को घरेलू उद्योग के अनुसार लिया गया है। ब्याज सहित एसजीए को घरेलू उद्योग के अनुसार लिया गया है। उत्पादन लागत पर *** की दर से पाटन मार्जिन पर विचार किया गया है। इस कार्यप्रणाली को अपनाकर बल्क फेनॉल के परिकलित सामान्य मूल्य की गणना *** अम. डालर प्रति मी. टन के रूप में की गई है। डिब्बाबंद सामग्री के लिए घरेलू उद्योग की पैकिंग सामग्री की लागत सामान्य मूल्य की गणना के लिए जोड़ दी गई है। इस पद्धति से डिब्बाबंद फेनॉल के लिए सामान्य मूल्य की गणना *** अम. डालर प्रति मी. टन के रूप में की गई है।

छ.1.2 असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

65. कारखाना निर्यात कीमत की गणना करने के लिए कोरिया गणराज्य से निर्यात हेतु डीजीसीआई एण्ड एस द्वारा सूचित आँकड़ों पर भरोसा किया गया है। डीजीसीआईएस के आँकड़ों में जाँच अवधि के दौरान बल्क और डिब्बाबंद दोनों प्रकार की सामग्री के आयात का पता चलता है। कारखाना निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़े, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए समायोजन किए गए हैं। उपर्युक्त पद्धति को अपनाकर बल्क सामग्री हेतु कारखाना निर्यात कीमत की गणना *** अम. डालर प्रति मी. टन के रूप में की गई है। डिब्बाबंद सामग्री के लिए कारखाना निर्यात कीमत की गणना *** अम. डालर प्रति मी. टन के रूप में की गई है।

छ.2. ताईवान

छ.2.1 ताईवान के लिए सामान्य मूल्य

66. ताईवान के किसी निर्यातक ने जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है। किसी उत्तर के अभाव में प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु पाटनरोधी नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है। सामान्य मूल्य के परिकलन हेतु बेंजीन की कीमत डीजीसीआईएस के आँकड़ों से और प्रोपीलीन की कीमत आईसीआईएस एलओआर एशिया से ली गई है। घरेलू उद्योग के खपत संबंधी मानकों और एसआईओएन पर भरोसा किया गया है। उपयोगिताओं के लिए विद्युत को छोड़कर खपत संबंधी मानदण्डों तथा घरेलू उद्योग की कीमत को लिया गया है, विद्युत के लिए दर निर्यातक देश में विद्युत दर की उपलब्ध सूचना के आधार पर ली गई है। परिवर्तन लागत को घरेलू उद्योग के अनुसार लिया गया है। ब्याज सहित एसजीए को घरेलू उद्योग के अनुसार लिया गया है। उत्पादन लागत पर *** की दर से पाटन मार्जिन पर विचार किया गया है। इस कार्यप्रणाली को अपनाकर बल्क फेनॉल के परिकलित सामान्य मूल्य की गणना *** अम. डालर प्रति मी. टन के रूप में की गई है। डिब्बाबंद सामग्री के लिए घरेलू उद्योग की पैकिंग सामग्री की लागत सामान्य मूल्य की गणना के लिए जोड़ दी गई है। इस पद्धति से डिब्बाबंद फेनॉल के लिए सामान्य मूल्य की गणना *** अम. डालर प्रति मी. टन के रूप में की गई है।

छ.2.2 असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

67. कारखाना निर्यात कीमत की गणना करने के लिए ताईवान से निर्यात हेतु डीजीसीआई एण्ड एस द्वारा सूचित आंकड़ों पर भरोसा किया गया है। डीजीसीआईएस के आंकड़ों में जाँच अवधि के दौरान बल्क और डिब्बाबंद दोनों प्रकार की सामग्री के आयात का पता चलता है। कारखाना निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़े, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए समायोजन किए गए हैं। उपर्युक्त पद्धति को अपनाकर बल्क सामग्री हेतु कारखाना निर्यात कीमत की गणना *** अम. डालर प्रति मी. टन के रूप में की गई है। डिब्बाबंद सामग्री के लिए कारखाना निर्यात कीमत की गणना *** अम. डालर प्रति मी. टन के रूप में की गई है।

छ.3 यूएसए

छ.3.1 यूएसए के लिए सामान्य मूल्य

68. यूएसए के किसी भी निर्यातक ने जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है और कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। किसी आंकड़े के अभाव में प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु पाटनरोधी नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है। इस प्रयोजनार्थ जाँच अवधि के लिए आईसीआईएस एलओआर (यूएस, गल्फ) में सूचित बेजीन तथा प्रोपीलीन की औसत कीमत सामान्य मूल्य के रूप में ली गई है। घरेलू उद्योग के खपत संबंधी मानकों और एसआईओएन पर भरोसा किया गया है। उपयोगिताओं के लिए जाँच अवधि के दौरान विद्युत को छोड़कर, जिसकी दर निर्यातक देश में विद्युत दर की उपलब्ध सूचना के आधार पर ली गई है; घरेलू उद्योग के खपत मानकों और कीमत पर विचार किया गया है। प्रिक्सन लागत को घरेलू उद्योग के अनुसार लिया गया है। व्याज सहित एसजीए को घरेलू उद्योग के अनुसार लिया गया है। उत्पादन लागत पर *** की दर से पाटन मार्जिन पर विचार किया गया है। इस कार्यप्रणाली को अपनाकर बल्क फेनॉल के परिकलित सामान्य मूल्य की गणना *** अम. डालर प्रति मी. टन के रूप में की गई है। डिब्बाबंद सामग्री के लिए घरेलू उद्योग की पैकिंग सामग्री की लागत सामान्य मूल्य की गणना के लिए जोड़ दी गई है। इस पद्धति से डिब्बाबंद फेनॉल के लिए सामान्य मूल्य की गणना *** अम. डालर प्रति मी. टन के रूप में की गई है।

छ.3.2 असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

69. कारखाना निर्यात कीमत की गणना करने के लिए यूएसए से निर्यात हेतु डीजीसीआई एण्ड एस द्वारा सूचित आंकड़ों पर भरोसा किया गया है। डीजीसीआईएस के आंकड़ों में जाँच अवधि के दौरान बल्क और डिब्बाबंद दोनों प्रकार की सामग्री के आयात का पता चलता है। कारखाना निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़े, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए समायोजन किए गए हैं। उपर्युक्त पद्धति को अपनाकर बल्क सामग्री हेतु कारखाना निर्यात कीमत की गणना *** अम. डालर प्रति मी. टन के रूप में की गई है। डिब्बाबंद सामग्री के लिए कारखाना निर्यात कीमत की गणना *** अम. डालर प्रति मी. टन के रूप में की गई है।

ज. पाटन मार्जिन

70. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के आधार पर निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नलिखित तालिका के अनुसार किया गया है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि किसी निर्यातक का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था और इसलिए सम्बद्ध देशों के सभी निर्यातकों को असहयोगी निर्यातक माना गया है :-

मिलियन अम. डालर (प्रति
मी. टन) में

निम्नलिखित के निर्यातक/ उत्पादक	सामान्य मूल्य- बल्क	सामान्य मूल्य- डिब्बाबंद	निर्यात कीमत- बल्क	निर्यात कीमत- डिब्बाबंद	पाटन मार्जिन- बल्क	पाटन मार्जिन- डिब्बाबंद	भारित पाटन मार्जिन
कोरिया गणराज्य	***	***	***	***	***	***	27.28%
ताइवान	***	***	***	***	***	***	21.20%
यूएसए	***	***	***	***	***	***	33.45%

71. इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन काफी अधिक और न्यूनतम स्तर से ज्यादा हैं।

झ. क्षति निर्धारण एवं कारणात्मक संबंध की जाँच**झ.1 घरेलू उद्योग के विचार**

72. घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं :-

- (क) जाँच अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से निर्यात कीमत पाटित स्तर पर रही है। इसके अलावा, आधार अवधि से लेकर जाँच अवधि तक इन कीमतों में निविष्टि की कीमतों में हुई वृद्धि के अनुपात में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।
- (ख) वर्ष 2004-05 में सुधार प्रदर्शित किए जाने के बाद घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री मात्रा तथा क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
- (ग) वर्ष 2004-05 में सुधार के बाद घरेलू उद्योग के लाभ/हानि (पीबीटी, पीबीआईटी तथा पीबीडीआईटी) सभी में पर्याप्त गिरावट प्रदर्शित हुई है।
- (घ) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। ऐसा इस तथ्य के कारण हुआ है कि पाटित आयातों ने भारत में माँग के पर्याप्त बाजार हिस्से पर कब्जा कर लिया है।
- (ङ) सम्बद्ध देशों में से प्रत्येक देश से हुए आयात द्वारा घरेलू उद्योग की कीमत में पर्याप्त स्तर पर कटौती हो रही है।
- (च) सम्बद्ध देशों से हुए आयातों द्वारा घरेलू उद्योग 2005-06 के दौरान और प्रस्तावित जाँच अवधि में कीमत में तेजी से कमी करने के लिए बाध्य हुआ है। इस प्रकार, आयातों से इस अवधि में कीमतों में कमी आई थी।
- (छ) घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तर में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है।
- (ज) वेतन एवं मजदूरी :- घरेलू उद्योग के वेतन एवं मजदूरी में वृद्धि हुई है।

- (झ) माँग एवं बाजार हिस्सा : - यद्यपि आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है तथापि घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है ।
- (ञ) वृद्धि : - अनेक मापदण्डों में घरेलू उद्योग की वृद्धि में ऋणात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है ।
- (ट) घरेलू उद्योग की वास्तविक क्षति हुई है और वह मात्रात्मक प्रभाव एवं कीमत प्रभाव के दुष्प्रकार में फैल गया है । विदेशी उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमता के परिणामस्वरूप भारतीय बाजार में सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा में वृद्धि होने से घरेलू उद्योग को बिक्री में घाटा उठाना पड़ा और बाजार हिस्सा गँवाया । इसके परिणामस्वरूप मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । बिक्री में हानि से घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में सम्बद्ध वस्तु की बिक्री करने के लिए अपनी घरेलू बिक्री कीमत घटाने के लिए बाध्य हुआ जिसके परिणामस्वरूप कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । निर्यातकों ने बिक्री कीमत में आगे और कमी कर दी तथा इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग ने बिक्री कीमत में और भी कमी की और यह प्रक्रिया जारी रखी । परिणामतः घरेलू उद्योग ने निर्यातक देशों के अनुचित व्यापार व्यवहारों की वजह से प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव तथा प्रतिकूल कीमत प्रभाव का सामना किया ।
- (ठ) सम्बद्ध देशों से हुए आयातों से घरेलू उद्योग को पहले ही हो रहे घाटे में वास्तविक क्षति बढ़ रही है ।
- (ड) आयात की मात्रा में समग्र रूप में पर्याप्त वृद्धि हुई है । आयातों में यह वृद्धि घरेलू उद्योग द्वारा ईष्टतम से कम कीमत पर भी अपनी सामग्री बेचने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हुई है । यदि घरेलू उद्योग ने कम कीमतों की पेशकश कर के इसमें कमी करने के प्रयास न किए होते तो आयातों में और अधिक वृद्धि हुई होती ।
- (ढ) कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है । समान कीमतें प्रस्तुत करने के बावजूद घरेलू उत्पाद तथा आयातित उत्पाद के बीच कीमत में सकारात्मक अंतर मौजूद है । शामिल उत्पाद के स्वरूप को देखते हुए घरेलू उत्पाद तथा आयातित उत्पाद के बीच कीमत में कोई अंतर उपभोक्ताओं को स्वीकार्य नहीं है और घरेलू उद्योग कीमत में कमी करने के लिए सतत दबाव में है । घरेलू उद्योग आयातित कीमतों से काफी अधिक कीमतों पर बिक्री नहीं कर सकता । घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प यह है कि बिक्री समान कीमतों पर की जाए । कीमत में मामूली अंतर भी इस प्रकार के उत्पाद के लिए काफी अधिक होता है ।
- (ण) याचिकाकर्ताओं ने घरेलू उद्योग पर संभावित प्रभाव के सम्बन्ध में सम्बद्ध देशों से विश्व भर को किए गए निर्यातों का व्यापक विश्लेषण किया । सम्बद्ध देशों के वैश्विक निर्यातों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है जिसका स्पष्ट अर्थ यह निकलता है कि विदेशी उत्पादकों के पास बेसी अप्रयुक्त क्षमताएँ हैं जिन्हें पाटित कीमतों पर भारत में उतारे जाने की संभावना है ।

अ.2. प्राधिकारी द्वारा जाँच

अ.2.1 क्षति का संचयी निर्धारण

73. नियमावली के अनुबंध II(iii) के अनुसार यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के आयातों की साथ-साथ पाटनरोधी जाँच की जा रही है तो प्राधिकारी के लिए केवल उस स्थिति में

ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना अपेक्षित होता है जब वह यह निर्धारित करता है कि

- (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में प्रमाणित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त 2% से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा 3% है तथा उनका संचयी हिस्सा समान वस्तु के आयातों के 7% से अधिक बनता है, और
- (ख) आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है ।

74. प्राधिकारी ने यह पाया है कि प्रत्येक देश के सम्बन्ध में पाटन मार्जिन 2% से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा भी 3% से अधिक है ।

75. आयातित उत्पादों और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के निर्धारण की दृष्टि से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि-

- (i) सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु का आयात एक समान टैरिफ वर्गीकरण के तहत किया गया है;
- (ii) प्राधिकारी ने यह पाया है कि आयातित सम्बद्ध वस्तु घरेलू रूप से उत्पादित फेनॉल की वाणिज्यिक रूप से स्थानापन्न है;
- (iii) प्राधिकारी को प्रस्तुत सूचना से इस बात का यथोचित संकेत मिलता है कि सम्बद्ध देशों से किए गए निर्यात उसी बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं क्योंकि ये समान उत्पाद हैं ।

76. अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयातित उत्पादों और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर घरेलू रूप से उत्पादित समान वस्तु पर सम्बद्ध वस्तु के आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है ।

77. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विभिन्न तर्कों को नोट किया है (अन्य हितबद्ध पार्टियों से कोई उत्तर नहीं मिला था) ।

78. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में निम्नलिखित दोनों की तथ्यपरक जाँच शामिल होगी :

- (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पादों के घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; तथा
- (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव ।

79. पाटित आयातों की मात्रा की जाँच करते समय प्राधिकारी के लिए इस बात की जाँच करनी अपेक्षित होती है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या उसकी खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत संबंधी प्रभाव के बारे में प्राधिकारी के लिए यह जाँच अपेक्षित होती है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के द्वारा कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा पर्याप्त स्तर तक कमी आई है या कीमत में ऐसी वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।

80. क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर सम्बद्ध वस्तु के पाटित आयातों के संचयी प्रभाव और घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों की जाँच की है ताकि क्षति और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, की मौजूदगी का मूल्यांकन किया जा सके।

81. चूंकि संबद्ध देशों से हुए निर्यातों के लिए पर्याप्त पाटन मार्जिन की पुष्टि की गई है इसलिए सम्बद्ध देशों से हुए समूचे निर्यातों को क्षति विश्लेषण एवं कारणात्मक संबंध की जाँच के प्रयोजनार्थ पाटित आयात माना गया है।

झ.2.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

82. प्राधिकारी ने डीजीसीआई एण्ड एस से सम्बद्ध वस्तु के आयातों के सौदेवार ब्यौरे एकत्र किए। आंकड़ों के अनुसार सम्बद्ध देशों से संचयी आयातों में समग्र रूप में और भारत में आयातों की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जाँच अवधि के दौरान कोरिया गणराज्य, ताईवान और यूएसए से आयात क्रमशः 10.66%, 27.21% और 20.59% रहे हैं। सम्बद्ध देशों से आयात अलग-अलग रूप में न्यूनतम सीमा से अधिक हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि क्षति अवधि की तुलना में जाँच अवधि में यूएसए से हुए आयातों के हिस्से में गिरावट आई है (वर्ष 2003-04 में 35.34% की तुलना में जाँच अवधि में घटकर 20.59%), तथापि आयातों में सम्बद्ध देशों का हिस्सा जो 2003-04 में 35.34% था जाँच अवधि में बढ़कर 58.46% हो गया है।

झ.2.2.1 आयात की मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा

	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06	जाँच अवधि
कोरिया गणराज्य	मी. टन	0	32	7917	9765
ताईवान	मी. टन	0	1985	24743	24920
यूएसए	मी. टन	23123	15410	23832	18853
संबद्ध देश	मी. टन	23123	17427	55591	53538
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	240	232
अन्य देश	मी. टन	42302	47607	37850	38040

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	89	90
कुल आयात	मी. टन	65425	65034	93441	91578
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	99.40	142.82	140

अ.2.2.2. आयातों में बाजार हिस्सा

कोरिया गणराज्य	%	0	0.05	7.51	10.66
ताइवान	%	0	3.05	26.48	27.21
यूएसए	%	35.34	23.70	25.50	20.59
संबद्ध देश	%	35.34	26.80	59.49	58.46
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	75.82	168.33	165.42
अन्य देश	%	64.66	73.20	40.51	41.54
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	113.22	62.65	64.24
घरेलू उद्योग का उत्पादन	मी. टन	40094	48403	28754	34275
संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	23123	17427	55591	53538
घरेलू उद्योग के उत्पादन के प्रतिशत के रूप में संबद्ध देशों से आयात	%	57.67	36	193.34	156.20

अ.3. माँग, उत्पादन एवं बाजार हिस्सा

अ.3.1. माँग में वृद्धि

अ.3.1.1 कैप्टिव खपत सहित माँग में वृद्धि

	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06	जाँच अवधि
घरेलू उद्योग	मी. टन	37583	44265	28143	32548
अन्य उत्पादक	मी. टन	35090	35410	28475	28289
कुल आयात	मी. टन	65425	65034	93441	91578
कुल माँग	मी. टन	138098	144710	150059	152415
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	104.79	108.66	110.36

अ.3.1.2 कैप्टिव खपत को छोड़कर माँग में वृद्धि

	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06	जाँच अवधि
घरेलू उद्योग	मी. टन	37583	44265	28143	32548
अन्य उत्पादक	मी. टन	32329	34099	26952	26561
कुल आयात	मी. टन	65425	65034	93441	91578

कुल माँग	मी. टन	135337	143399	148536	150687
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	105.96	109.75	111.34

83. सम्बद्ध वस्तु की माँग का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री (कैप्टिव बिक्री सहित) और सभी देशों से हुए समस्त आयातों को जोड़कर किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष से लेकर जाँच अवधि तक सम्बद्ध वस्तु की माँग में वृद्धि होती रही थी। जाँच अवधि के दौरान इसमें आधार वर्ष अर्थात् 2003-04 की तुलना में 10% की वृद्धि हुई।

84. कैप्टिव बिक्री को छोड़कर सम्बद्ध वस्तु की माँग में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। आधार वर्ष की तुलना में इसमें 11% की वृद्धि हुई।

85. घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में सम्बद्ध देशों से आयातों में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। आधार वर्ष 2003-04 में घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में सम्बद्ध देशों से आयात केवल 58% थे जो जाँच अवधि में % के रूप में बढ़कर 156.20% हो गए।

अ.4. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन एवं क्षमता उपयोग

	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06	जाँच अवधि
स्थापित क्षमता	मी. टन	40000	40000	40000	40000
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	100.00	100.00	100.00
उत्पादन	मी. टन	40094	48403	28754	34275
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	120.72	71.72	85.68
क्षमता उपयोग (%)	%	100	121	72	86
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	120.72	71.72	85.68

86. क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग के आँकड़ों से यह पता चलता है कि वर्ष 2003-04 में घरेलू उद्योग की क्षमता 40,000 मी. टन की थी और उसमें जाँच अवधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वर्ष 2003-04 में सम्बद्ध वस्तु का उत्पादन 40094 मी. टन का हुआ था जो वर्ष 2004-05 में 48403 मी. टन के स्तर तक बढ़ने के बाद वर्ष 2005-06 में घटकर 28754 मी. टन हो गया और जाँच अवधि में यह 34275 मी. टन रहा। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग, जो 2004-05 के दौरान 121% था, आधार वर्ष 2003-04 में 100% की तुलना में जाँच अवधि में घटकर 86% रह गया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2005-06 में उत्पादन में प्रमुख कच्ची सामग्री की खरीद में आई कठिनाइयों के कारण कम्पनी द्वारा लम्बे समय तक तालाबन्दी के कारण गिरावट आई। तथापि, जाँच अवधि में कम्पनी ने पूर्ण उत्पादन पुनः शुरू किया और वह वर्ष 2003-04 और 2004-05 में प्राप्त मात्रा तक उत्पादन कर सकी। जाँच अवधि के दौरान यद्यपि संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता तक उत्पादन करने के लिए तैयार था तथापि, वह केवल 86% क्षमता तक ही प्रचालन कर सका।

अ.4.1. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा

	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06	वार्षिक जाँच अवधि
घरेलू उद्योग	मी. टन	37583	44265	28143	32548
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	117.78	74.88	86.60

87. बिक्री संबंधी आंकड़ों से यह पता चलता है कि वर्ष 2003-04 के दौरान घरेलू उद्योग ने 37583 मी. टन सम्बद्ध वस्तु की बिक्री की जो जाँच अवधि में घटकर 32548 मी. टन रह गई। इस प्रकार, आधार वर्ष 2003-04 की तुलना में घरेलू उद्योग की बिक्री घटकर 87% रह गई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग वर्ष 2004-05 के दौरान 44265 मी. टन की बिक्री कर सका और जाँच अवधि में हुई बिक्रियाँ पूर्व में प्राप्त इन स्तरों से काफी कम थीं।

88. घरेलू उद्योग की बिक्री से संबंधित उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि आधार वर्ष 2003-04 की तुलना में जाँच अवधि के दौरान बिक्री में 13% तक की गिरावट आई यद्यपि जाँच अवधि के दौरान बिक्रियाँ वर्ष 2005-06 में हुई बिक्रियों की तुलना में अधिक रही थी। जैसा कि ऊपर नोट किया गया है वर्ष 2005-06 के दौरान उत्पादन में कम्पनी द्वारा लम्बे समय तक की गई तालाबन्दी के कारण गिरावट आई और ऐसा ही बिक्री के मामले में हुआ। यह भी नोट किया जाता है कि वर्ष 2004-05 के दौरान घरेलू उद्योग जाँच अवधि में हुई 32548 मी. टन की बिक्री की तुलना में 44265 मी. टन की बिक्री कर सका।

अ.4.2. कैप्टिव खपत सहित माँग एवं बाजार हिस्सा

	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06	जाँच अवधि
घरेलू उद्योग	मी. टन	37583	44265	28143	32548
अन्य उत्पादक	मी. टन	35090	35410	28475	28289
कुल आयात	मी. टन	65425	65034	93441	91578
कुल माँग	मी. टन	138098	144710	150059	152415
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	104.79	108.66	110.36
माँग में बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	27.21	30.59	18.75	21.35
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	112.40	68.91	78.46
अन्य उत्पादक	%	25.41	24.47	18.98	18.56
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	96.30	74.68	73.04
कोरिया गणराज्य	%	0.00	0.02	4.68	6.41
ताईवान	%	0.00	1.37	16.49	16.35
यूएसए	%	16.74	10.65	15.88	12.37
संबद्ध देश	%	16.74	12.04	37.05	35.13
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	71.92	221.25	209.86

अन्य देशों से आयात	%	30.63	32.90	25.22	24.96
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	107.40	82.34	81.49

झ.4.3. कैप्टिव खपत रहित माँग एवं बाजार हिस्सा

	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06	जाँच अवधि
घरेलू उद्योग	मी. टन	37583	44265	28143	32548
अन्य उत्पादक	मी. टन	32329	34099	26952	26561
कुल आयात	मी. टन	65425	65034	93441	91578
कुल माँग	मी. टन	135337	143399	148536	150687
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	105.96	109.75	111.34
माँग में बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	27.77	30.87	18.95	21.60
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	111.16	68.23	77.78
अन्य उत्पादक	%	23.89	23.78	18.14	17.63
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	99.55	75.96	73.80
कोरिया गणराज्य	%	0.00	0.02	4.72	6.48
ताईवान	%	0.00	1.38	16.66	16.54
यूएसए	%	17.09	10.75	16.04	12.51
संबद्ध देश	%	17.09	12.15	37.43	35.53
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	71.13	219.05	207.90
अन्य देशों से आयात	%	31.26	33.20	25.48	25.24
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	106.21	81.52	80.74

89. भारत में खपत के संबंध में संबद्ध देशों से आयात 2003-04 में 16.74% से पर्याप्ततः बढ़कर जाँच अवधि में 35.13% हो गए।

90. संबद्ध वस्तु की माँग में लगातार वृद्धि हुई है। आधार वर्ष 2003-04 की तुलना में जाँच अवधि में माँग 10% अधिक रही थी। घरेलू उद्योग का हिस्सा जो 2003-04 में 27.21% था, जाँच अवधि में घटकर 21.35% रह गया। इसी अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा जो 2003-04 में 16.74% था, जाँच अवधि में बढ़कर 35.13% हो गया। यह नोट किया जाता है कि पाटित आयातों ने न केवल माँग की वृद्धि में सहायता डाली है अपितु घरेलू उद्योग को भी अस्त-व्यस्त कर दिया।

91. संबद्ध वस्तु की माँग (कैप्टिव बिक्री को छोड़कर) में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई देती है। आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में इसमें 11% की वृद्धि हुई। प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग का हिस्सा जो 2003-04 में 28% था, जाँच अवधि में घटकर 22% रह गया। इसी

अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों का हिस्सा जो 2003-04 में 17% था, जाँच अवधि में बढ़कर 36% हो गया।

झ.5 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

92. नियम 18 के उप नियम (2) में किए गए उल्लेख के अनुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात की जाँच करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के द्वारा कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा पर्याप्त स्तर तक कमी आई है या कीमत में ऐसी वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।

93. सम्बद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जाँच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संबंध में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ उत्पादन की भारित औसत लागत, भारित औसत निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की तुलना सम्बद्ध देशों से आयातों की पहुँच लागत के साथ की गई है।

झ. 5.1. विचाराधीन अवधि की तुलना में कीमत का मूल्यांकन

इकाई	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06	जाँच अवधि
बिक्री की लागत	रु./मी. टन	36851	48871	49093	50196
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	132.62	133.22	136.21
बिक्री कीमत (एनएसआर)	रु./मी. टन	43249	63525	52175	53030
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	146.88	120.64	122.62

झ.6. कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री संबंधी प्रभाव

जाँच अवधि	इकाई	बल्क	डिब्बाबंद	कुल भारित औसत (बल्क + डिब्बाबंद)
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./मी. टन	51925	57810	53030
पहुँच मूल्य				
कोरिया गणराज्य	रु./मी. टन	47699	52980	48788
ताईवान	रु./मी. टन	49072	65874	51437
यूएसए	रु./मी. टन	47441	74539	49487
कुल संबद्ध देश	रु./मी. टन	48513	67300	50267
कीमत कटौती				
कोरिया गणराज्य	रु./मी. टन	4226	4830	4242
ताईवान	रु./मी. टन	2253	-8064	1593
यूएसए	रु./मी. टन	4484	-16729	3543

कुल संबद्ध देश	रू./मी. टन	3412	-9490	2763
कीमत कटौती (%)				
कोरिया गणराज्य	%	8.14%	8.36%	8.00%
ताईवान	%	4.34%	-13.95%	3.00%
यूएसए	%	8.64%	-28.94%	6.68%
कुल संबद्ध देश	%	6.57%	-16.42%	5.21%
क्षतिरहित कीमत	रू./मी. टन	56494	61873	57532
कम कीमत पर बिक्री				
कोरिया गणराज्य	रू./मी. टन	8795	8893	8798
ताईवान	रू./मी. टन	6822	-4001	6130
यूएसए	रू./मी. टन	9053	-12666	8090
कुल संबद्ध देश	रू./मी. टन	7981	-5427	7307
कम कीमत पर बिक्री (%)				
कोरिया गणराज्य	%	15.57%	14.37%	15.29%
ताईवान	%	12.08%	-6.47%	10.66%
यूएसए	%	16.02%	-20.47%	14.06%
कुल संबद्ध देश	%	14.13%	-8.77%	12.70%

अ.6.1 हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्क

94. कुछ हितबद्ध पार्टियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी को प्रत्येक देश के लिए अलग-अलग कीमत कटौती का खुलासा करना चाहिए। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी ने प्रारम्भिक जाँच परिणामों में पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आयातों के पहुँच मूल्य का खुलासा नहीं किया है ताकि वे पूर्ववर्ती वर्षों की कीमत के रुझानों की तुलना कर सकें।

अ.6.2 प्राधिकारी द्वारा जाँच

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमों के तहत समूची क्षति अवधि के लिए कीमत कटौती का निर्धारण अपेक्षित नहीं होता है। तथापि, तर्क पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती वर्षों के लिए भी कीमत कटौती का निर्धारण किया है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :

	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06	जाँच अवधि
निवल बिक्री प्राप्ति	रू./मी. टन	43249	63525	52175	53030
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	146.88	120.64	122.62
पहुँच मूल्य					
कोरिया गणराज्य	रू./मी. टन		45537	51471	48788
ताईवान	रू./मी. टन		84183	50760	51437
यूएसए	रू./मी. टन	38174	61824	54938	49487
कुल संबद्ध देश	रू./मी. टन	38174	64341	52641	50267
कीमत कटौती					
कोरिया गणराज्य	रू./मी. टन	-	17988	704	4242

ताईवान	रु./मी. टन	-	-20658	1415	1593
यूएसए	रु./मी. टन	5075	1701	-2763	3543
कुल संबद्ध देश	रु./मी. टन	5075	-816	-466	2763
कीमत कटौती (%)					
कोरिया गणराज्य	%	-	28.32%	1.35%	8.00%
ताईवान	%	-	-32.52%	2.71%	3.00%
यूएसए	%	11.74%	2.68%	-5.30%	6.68%
कुल संबद्ध देश	%	11.74%	-1.28%	-0.89%	5.21%

96. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति निकालते समय घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत रिबेट, छूट और कमीशन तथा भुगतान किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर रिबेट प्रदान किया गया है।

97. कीमत कटौती का निर्धारण समूची जाँच अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से पाटित आयातों के भारित औसत पहुँच मूल्य की उसी अवधि के लिए घरेलू उद्योग की भारित औसत निवल बिक्री प्राप्ति के साथ तुलना कर के किया गया है। इस प्रयोजनार्थ आयातों के पहुँच मूल्य की गणना 1% हैंडलिंग प्रभार और लागू मूल सीमाशुल्क को सम्बद्ध देशों से आयात कीमतों के डीजीसीआई एण्ड एस आंकड़ों में सूचित मूल्य में जोड़कर की गई है। जाँच अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से कीमत कटौती 4-10% के बीच रही थी।

98. कम कीमत पर बिक्री के प्रयोजनार्थ सम्बद्ध देशों से आयातों की भारित औसत पहुँच कीमत की तुलना जाँच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत के साथ की गई है। इससे यह पता चलता है कि कम कीमत पर बिक्री 12-17% के बीच रही थी।

अ. प्रकटन विवरण के पश्चात अनुरोध

अ.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

99. घरेलू उद्योग ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके सभी तर्कों को रिकॉर्ड में ले लिया गया है और उन्हें प्रकटन विवरण में समुचित रूप से प्रकाशित किया गया है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि निर्धारित राशि के संबंध में शुल्क भारतीय रूपए में संस्तुत किया जाए क्योंकि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक बेंचमार्क कीमत/अलग-अलग शुल्क की सिफारिश करना उचित नहीं होगा कि कच्ची सामग्री की कीमतों में लगातार और काफी अधिक उतार-चढ़ाव रहा है। उन्होंने आगे इस आधार पर सकल नियत परिसम्पत्तियों पर विचार करते हुए क्षतिरहित कीमत के निर्धारण की माँग की है कि मूलभूत संयंत्र और उपकरणों का अब पूर्णतः मूल्य हास कर दिया गया है और प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली का यह अर्थ निकलता है कि घरेलू उद्योग को केवल इस कारण की वजह से उत्पादन और उत्पाद की बिक्री से कोई लाभ नहीं कमाना चाहिए कि संगत नियत परिसम्पत्तियों का अब पूर्ण मूल्य हास हो गया है।

अ.2. घरेलू उद्योग के अलावा अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोध

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य, ताईवान या यूएसए में संबद्ध वस्तु के किसी भी उत्पादक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। तथापि, संबद्ध वस्तु के प्रयोक्ताओं लैमिनेट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन और मै. सेंचुरी प्लाई लि. ने निम्नलिखित मुद्दे उठाते हुए जाँच समाप्त करने का अनुरोध किया है।

101. लैमिनेट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

(i) इस तथ्य पर कि एसआई ग्रुप द्वारा संबद्ध वस्तु का पर्याप्त मात्रा में आयात किया गया था, वर्तमान मामले की शुरुआत के समय विचार किया जाना चाहिए न कि ऐसे किसी बाद के चरण पर। प्राधिकारी से ऐसे तथ्यों को छिपाना वर्तमान कार्रवाई को समाप्त करने का एक अच्छा आधार होना चाहिए। ऐसे आयातों को किसी भी हालत में अनुबंध II के तहत विश्लेषण में शामिल नहीं किया जा सकता। अतः समूची प्रक्रिया निरर्थक है।

(ii) हम पैरा 17 की विषय वस्तु का उत्तर देने में असमर्थ रहे हैं क्योंकि हमने शुल्क के बेंचमार्क स्वरूप पर कोई अनुरोध नहीं किया था। पैरा 18 के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बात का उल्लेख किए बिना एसोसिएशन के अनुरोध को अस्वीकृत करने की माँग की कि इस अनुरोध को अस्वीकृत किया जाना है अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इन मुद्दों पर कोई उत्तर या कोई अन्य टिप्पणी प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं।

(iii) तालाबन्दी और घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर उसके प्रभाव के मुद्दे की जाँच अपेक्षित थी और ऐसा सही संदर्भ में नहीं किया गया है। प्राधिकारी को उचित क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ समायोजित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

(iv) प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जाँच परिणामों की जरूरत के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लेने के बाद इन्हें जारी किया गया था। हमारा सादर निवेदन है कि ऐसे निष्कर्ष के समर्थन में जाँच परिणामों के कारण रिकॉर्ड से स्पष्ट नहीं होते हैं। अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए प्रारम्भिक जाँच परिणामों में ऐसे कारण बताना अपेक्षित था। ऐसे निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए ऐसे कारणों के अभाव में प्रारम्भिक जाँच परिणाम विधिसम्मत नहीं हैं। इसी प्रकार, हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिले हैं जहाँ निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ऐसे निष्कर्षों का कारण दर्ज किए बिना निष्कर्ष दर्ज किए हैं।

(v) प्रकटन विवरण से हमें यह पता चलता है कि सेंचुरी प्लाई लि. ने उत्तर दिया और अपने लिखित अनुरोध दायर किए। हमारे अनुरोध के बावजूद उन्हें हमारे लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पार्टियों के साथ हुआ पत्राचार भी सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध नहीं है। ऐसी सूचना के अभाव में हितबद्ध पार्टियों के अधिकारों के प्रति गंभीर भेदभाव किया गया है जिससे वे आंकड़ों पर कारगर टिप्पणियाँ प्रस्तुत नहीं कर सकें और हितबद्ध पार्टियों के

समर्थन में नियमों में यथानिर्धारित निर्धारण करने के लिए सूचना प्राकृतिक न्याय संबंधी कानून के स्पष्टतः प्रतिकूल होगी ।

(vi) हम प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए आंकड़ों पर टिप्पणी देने में असमर्थ हैं क्योंकि हमारे पूर्ववर्ती अनुरोधों में निवेदन के बावजूद ये सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध नहीं कराए गए थे । हमें विश्वास है कि प्राधिकारी को उन्हें गोपनीय आधार पर उपलब्ध नहीं कराया गया था और उन्हें रोका नहीं गया है क्योंकि नियम 7 के उपबंधों का सहारा डीजीसआई एंड एस द्वारा नहीं लिया जा सकता । यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना है और इसे हितबद्ध पार्टियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

(vii) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने बताया है कि प्रकटन विवरण में *** का चिह्न गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा प्रस्तुत सूचना का द्योतक है । तथापि, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह पता चल सके कि आवेदक ने उक्त सूचना को गोपनीय रखने का अच्छा कारण प्रदर्शित किया था । इस सम्बन्ध में, प्राधिकारी को जाँच की शुरुआत से ही यह बताया गया था कि गोपनीयता के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है और इसका उपयोग कानून की मूल भावना के प्रतिकूल किया जा रहा है । किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसा कोई उल्लेख नहीं होता है जिससे यह संकेत मिले कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने गोपनीयता के पहलू पर वस्तुतः ध्यानपूर्वक विचार किया था । यह पहला अवसर है जब प्रकटन विवरण में सरसरी तौर पर यह उल्लेख किया गया है कि हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने गोपनीय रूप से विचार किया है । निर्यातक और अन्य हितबद्ध पार्टियाँ इस बात पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या निर्दिष्ट प्राधिकारी के विवरण का उपयोग कानूनी उपबंधों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार किया गया है ।

(viii) वर्तमान कार्यवाहियों में अत्यंत गोपनीयता का दावा किया गया है और उसकी अनुमति दी गई है । आगे यह आरोप लगाया गया है कि सार्वजनिक फाइल में यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है कि प्राधिकारी ने गोपनीयता के व्यवहार का सावधानीपूर्वक अनुपालन किया है और सार्वजनिक फाइल पर उचित सूचीकरण भी नहीं है ।

(ix) बेंजीन की कीमतों और प्रोपीलीन की कीमतों, विद्युत लागत, कमीशन, भाड़े, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, भाड़ा लागत से संबंधित आंकड़ों के बारे में आईसीआईएस एलओआर के भरोसे को गोपनीय रखा गया है जिस पर आपत्ति उठाई गई है । यह भी उल्लेख किया गया है कि आईसीआईएस एलओआर के आंकड़ों से कच्ची सामग्री की कीमत के उपयोग हेतु औचित्य उस समय प्रदान नहीं किया गया है जब स्वयं फेनॉल की कीमत उपलब्ध थी ।

(x) बीआईएफआर की स्थिति में एसिटोन के मामले में अंतिम जांच परिणामों पर भरोसे को चुनौती दी गई है और यह सुझाव दिया गया है कि एचओसीएल को बीआईएफआर से पूर्व अपने मामले पर नवीनतम स्थिति उपलब्ध कराने के लिए बुलाया जाए । यह भी बताया गया है कि चूँकि

एचओसीएल से प्रत्येक सूचना आरटीआई के तहत प्राप्त की जा सकती है इसलिए किसी भी सूचना को गोपनीय रखे जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(xi) अपूर्णतः पत्रों और उनके उत्तरों के रूप में कार्यवाही के दौरान प्राप्त अतिरिक्त सूचना, टिप्पणियों/ आपत्तियों के लिए सार्वजनिक फाइलें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

(xii) सामान्य मूल्य की गणना से संबंधित विभिन्न निविष्टियों के संबंध में निकाले गए आंकड़ों, खासकर डीजीसीआई एण्ड एस के आंकड़ों और आईसीआई एसएलआर से प्रोपीलीन की कीमतों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अन्य निविष्टियों को सार्वजनिक करने की माँग की गई है।

(xiii) भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशी भाड़े, भाड़ा व्यय, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए निकाले गए समायोजनों के बाद डीजीआईएस के आंकड़ों के आधार पर निकाली गई अंतिम निर्यात कीमत को सार्वजनिक करने की माँग की गई है।

(xiv) आंकड़ों के संबंध में वास्तविक पाटन मार्जिन को प्रकटित करने की माँग की गई है और तत्पश्चात् हितबद्ध पार्टियों से नए सिरे से नई टिप्पणियाँ माँगी जानी चाहिए। वास्तविक संख्या में एनआईपी निकालने की वास्तविक गणनाओं का भी खुलासा करने की माँग की गई है।

(xv) घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई बताई गई संशोधित क्षति संबंधी सूचना का खुलासा करने की माँग की गई है और आगे यह माँग की गई है कि उसका खुलासा करने के बाद हितबद्ध पार्टियों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए क्योंकि पूर्व में दिया गया एक अवसर कानून एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में की गई परिकल्पना के अनुसार नहीं था। यह आरोप लगाया गया है कि एचओसीएल द्वारा पिछले 10 वर्ष में कभी भी कोई लाभ अर्जित न करने के बावजूद लगाई गई पूंजी पर 22% आय की माँग करना इस बात का संकेतक है कि एचओसीएल का अस्तित्व या तो आत्मरक्षा शुल्क या पाटनरोधी शुल्क के रूप में या टैरिफ के जरिए सुरक्षा के रूप में बाह्य सहायता पर ही निर्भर है। उन्होंने उन कारणों की माँग की है कि डीजीएडी व्यापार सूचना सं. 2/24, तारीख 12.5.2004 के संबंध में वित्त वर्ष 2002-03 के लिए सूचना क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(xvi) उन्होंने एक मुद्दा यह उठाया है कि क्या निर्दिष्ट प्राधिकारी ने बीआईएफआर की कार्यवाहियों का समग्र रिकॉर्ड माँगा था। उन्होंने आरोप लगाया है कि जाँच में प्रयुक्त आयत आंकड़ों की सॉफ्ट कॉपी उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं।

(xvii) यह आरोप लगाया गया है कि सभी पार्टियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर संबंधी अनुरोध उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर सभी उत्तरों के अगोपनीय रूपांतर उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

(xviii) यह बताया गया है कि प्रकटन विवरण में पहली बार कुछ नए तथ्य शामिल किए गए हैं और हितबद्ध पार्टियों को इसकी कभी सूचना नहीं दी गई थी।

(xix) यह आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा किए गए विस्तृत अनुरोधों के अनेक भागों को प्रकटन विवरण में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। रोचक तथ्य यह है कि यद्यपि प्रकटन विवरण में घरेलू उद्योग के अपुष्टिकृत अनुरोधों को भी दर्ज किया गया है तथापि, एसोसिएशन एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत खण्डन तथा तर्कों को प्रस्तुत न कर अजीब स्थिति पैदा कर दी गई है।

(xx) प्रकटन विवरण में इस आशय के विवरण कि समस्त सूचना सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध थी, रिकॉर्ड देखकर विपरीत स्थिति का पता चलता है।

(xxi) सार्वजनिक फाइल के निरीक्षण और प्रत्युत्तर विवरणों की प्रतियों के लिए किए अनुरोधों का अब तक जवाब नहीं दिया गया है। सार्वजनिक फाइल में कोई पृष्ठ सं., सूची आदि नहीं दी गई है। ऐसा कोई दृष्टिकोण माननीय सैस्टेट द्वारा पूर्ववर्ती मामलों में निर्धारित दिशानिर्देश के प्रतिकूल है।

(xxii) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आंकड़ों को संशोधित किए जाने के बाद नए सिरे से सुनवाई के अनुरोध की अनुमति नहीं दी है। प्राकृतिक न्याय और प्रशासनिक विधि के सिद्धांतों के अनुसार नए सिरे से सुनवाई अनिवार्य थी। सुविधा संतुलन में भी यह अपेक्षित है कि किए गए अनुरोध की अनुमति दी जाए क्योंकि नए सिरे से सुनवाई की अनुमति दिए जाने की प्रार्थना स्वीकार करने पर घरेलू उद्योग के हित के प्रति कोई भेदभाव नहीं होगा। तथापि, यदि इसकी अनुमति नहीं दी जाती है तो आयातकों/निर्यातकों तथा प्रयोक्ता उद्योग के हित को गम्भीर तथा अपूरणीय क्षति और हानि होगी।

(xxiii) इस बात का गलत उल्लेख किया गया है कि “यह अधिसूचना नियम 5 के उपबंधों के अनुसार शुरू की गई थी।” एसोसिएशन ने जाँच शुरूआत संबंधी प्रक्रिया में कमियों और सुधार न किए जाने योग्य त्रुटियों और नियम 5 की अपेक्षाओं के अननुपालन का समय-समय पर अपने लिखित पत्रों में उल्लेख करते हुए व्यापक अनुरोध किए थे। आश्चर्य की बात यह है कि प्राधिकारी ने इन्हें “आवश्यक तथ्य” नहीं माना है।

(xxiv) यह विवरण कि “सूचना प्रस्तुत करने और जाँच शुरूआत पर टिप्पणियाँ करने और तत्पश्चात जाँच के प्रत्येक चरण में पर्याप्त अवसर दिया गया था” इस मामले के तथ्यों के पूर्णतः प्रतिकूल है। इसके समर्थन में हम उपर्युक्त अनुरोधों पर भरोसा करते हैं। हम आपका ध्यान अपने उन अनुरोधों की तरफ भी आकर्षित करते हैं जिनमें यह उल्लेख किया गया था कि घरेलू उद्योग ने वास्तव में उन हितबद्ध पार्टियों के नाम रोक लिए हैं जिनके साथ उन्होंने फेनॉल के नियमित सौदे किए थे।

(xxv) पैरा 44 में इस आशय का उल्लेख करना पुनः गलत है कि “... प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि उत्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन खराब हुआ है....

इस प्रकार संचयी रूप से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।” यह नोट करना संगत है कि एसोसिएशन द्वारा किए गए गंभीर अनुरोधों पर प्राधिकारी ने ध्यान नहीं दिया है और इन्हें प्रकटन विवरण का एक भाग भी नहीं बनाया है।

(xxvi) एसोसिएशन द्वारा व्यक्त विचारों को प्रकटन विवरण में चुनिंदा ढंग से पुनः प्रस्तुत किया गया है। हमारे पत्रों में उल्लिखित अधिकांश महत्वपूर्ण पहलुओं को भी प्रकटन विवरण में रिकॉर्ड नहीं किया गया है।

102. उचित व्यापार व्यवहार के संबंध में सेंचुरी प्लाई की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में आयातक प्रश्नावली के उत्तर के रूप में सेंचुरी प्लाई द्वारा प्रस्तुत सूचना को अस्वीकृत कर दिया है क्योंकि प्राधिकारी के अनुसार उसमें सही स्थिति प्रदर्शित नहीं हो रही है। अनुरोध है कि यद्यपि यह माना जाता है कि कम्पनी द्वारा प्रस्तुत सूचना में कुछेक टंकण संबंधी त्रुटियाँ होती हैं तथापि प्राधिकारी ने किसी स्पष्टीकरण हेतु कम्पनी संबंधी कोई पत्र जारी नहीं किया है। अतः आयातक को कोई अवसर प्रदान किए बिना जाँच की समाप्ति पर उस सूचना को पूर्णतः अस्वीकृत करना जो अन्यथा भरोसेमंद और समर्थनकारी कागजों से युक्त है, निर्दिष्ट प्राधिकारी के भाग पर अत्यंत अनुचित है।

(ii) यह एक स्वीकृत तथ्य है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए याचिका एचओसीएल तथा एसआई ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी किन्तु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत संयुक्त आंकड़ों का अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पार्टियों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। अनुरोध है कि प्राधिकारी ने प्रारंभिक जाँच परिणामों और प्रकटन विवरण में स्वयं यह नोट किया है कि याचिकाकर्ता को एसआई ग्रुप से संबंधित सूचना अलग करने के बाद क्षति संबंधी सूचना का निर्देश दिया गया था किन्तु शुरुआत में दायर की गई सूचना का इस हेतु बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद हितबद्ध पार्टियों के साथ आदान-प्रदान नहीं किया गया था। बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एसआई ग्रुप से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(iii) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एसआई ग्रुप द्वारा किए गए आयातों की मात्रा को भी संबद्ध देशों से हुए आयातों की कुल मात्रा से अलग नहीं किया है जिससे आयातों की कुल मात्रा में और अधिक वृद्धि हो गई है। अनुरोध है कि संबद्ध देशों से आयातों की कुल मात्रा में वृद्धि का एक कारण एसआई ग्रुप द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पर्याप्त मात्रा में आयात करना रहा है जैसा कि प्राधिकारी ने अपने जाँच परिणाम में दर्ज किया है और इसलिए क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग/याचिका के समर्थक द्वारा किए गए आयातों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए था।

(iv) अनुरोध है कि राजपत्र में सूचना का प्रकाशन एक मुद्दा नहीं है बल्कि वास्तविक मुद्दा किसी प्रकार के विरोध से बचने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा सम्बद्ध वस्तु के वास्तविक प्रयोक्ताओं/आयातकों के नामों को जान-बूझकर छिपाने का है। यह सच है कि याचिकाकर्ता ने वास्तविक प्रयोक्ताओं के

नामों की जानकारी होने के बावजूद उनकी सूचना प्राधिकारी को नहीं दी जिससे याचिकाकर्ता की मंशा के बारे में गंभीर प्रश्न चिह्न लग जाता है और कारगर भागीदारी करने के लिए हितबद्ध पार्टियों के अधिकार का उल्लंघन होता है।

(v) याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन की दीर्घावधिक बन्दी/स्थगन को याचिकाकर्ता ने जान-बूझकर छिपाया है। वार्षिक रिपोर्ट में उसके केवल उत्पादन से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए याचिका में सम्पूर्ण तथ्य उपलब्ध कराने के लिए याचिकाकर्ता की जिम्मेवारी/दायित्व समाप्त नहीं होता है।

(vi) याचिकाकर्ता द्वारा क्षति संबंधी सूचना में भी इस तथ्य का खुलासा नहीं होता है और इसके विपरीत तालाबन्दी की अवधि के लिए कोई सूचना जाँच अवधि तथा पूर्ववर्ती 3 वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय आंकड़ों के साथ इस स्पष्ट कारण की वजह से उपलब्ध नहीं कराई गई है जिससे कि नामों को छिपाया जा सके और क्षति संबंधी सूचना विकृत रूप में प्रस्तुत की जा सके। इसके अलावा, तालाबन्दी के दौरान आयातों का याचिका में अथवा प्रारंभिक जांच परिणामों/प्रकटन विवरण में न तो याचिकाकर्ता और न ही प्राधिकारी द्वारा कहीं भी विश्लेषण किया गया है। याचिकाकर्ता ने इसे छिपाया था जिसे मध्यावधि समीक्षा के अंतिम जांच परिणामों से भी देखा जा सकता है जिसमें वह बड़ी चतुराई से गायब है।

(vii) क्षति के मुद्दे के संबंध में हम एक बार पुनः जाँच की कार्यवाही के दौरान पूर्व में दायर अपने अनुरोध को दोहराते हैं, जो निम्नानुसार है :

(viii) याचिकाकर्ता ने जाँच अवधि को लक्ष्य बनाकर जान-बूझकर याचिका दायर की है जो एचओसीएल द्वारा संयंत्र की जान-बूझकर तालाबन्दी से पहले विकृत हो चुकी है। याचिकाकर्ता ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति को उजागर करने के एक प्रयास में उसकी तालाबन्दी की अवधि के तुरंत बाद की अवधि चुनी है। घरेलू उद्योग ने सर्वप्रथम एक छिटपुट कारण कि कच्ची सामग्री उपलब्ध नहीं थी जिससे अल्प आपूर्ति के बाजार में स्थिति गंभीर बन गई थी और सभी प्रयोक्ताओं को झटका लगा था, काफी लम्बी अवधि तक अपने संयंत्र की तालाबन्दी की। घरेलू बाजार में फेनॉल की कमी होने से संबद्ध देशों से वस्तु का आयात करना पड़ा। यह नोट किया जाना चाहिए कि तालाबन्दी से पूर्व सभी आर्थिक संकेतकों से सकारात्मक वृद्धि का पता चलता था और घरेलू उद्योग अच्छी स्थिति में कार्य कर रहा था। अप्रैल, 05- जून, 05 की अवधि तक तालाबन्दी से घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हुआ है। इसके अलावा, एसआई ने अपनी खुद की कैप्टिव खपत हेतु संबद्ध वस्तु का आयात किया है। आयातों के मात्रात्मक प्रभाव का निर्धारण करते समय एसआई द्वारा किए गए आयातों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(ix) घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में समर्थ रहा है। प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित कीमत कटौती केवल 5-10% है। प्राधिकारी से हमारा अनुरोध है कि वह प्रत्येक देश के लिए अलग-अलग कीमत कटौती का खुलासा करे। इसके अलावा, प्रारंभिक जांच परिणामों में पूर्ववर्ती वर्षों के

लिए आयातों के पहुँच मूल्य का प्रकटन नहीं किया गया है ताकि हम पूर्ववर्ती वर्षों की कीमत प्रवृत्ति की तुलना कर सकें।

(x) आगे यह अनुरोध है कि तालाबन्दी की अवधि को ध्यान में रखते हुए क्षति विश्लेषण के संबंध में प्राधिकारी द्वारा लगाया गया कोरा अनुमान वास्तविकता से काफी दूर है।

(xi) प्रकटण विवरण में यह उल्लेख है कि :

“ घरेलू उद्योग ने वर्ष 2005-06 में संयंत्र की तालाबन्दी का सामना किया था। इस बात का अनुमान लगाते हुए घरेलू उद्योग ने तालाबन्दी की अवधि के दौरान उसी दर से उत्पादन किया होता जैसा कि उसने 2005-06 में उत्पादन किया था और समस्त उत्पादन की बिक्री की थी उसने विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध कराया है जो निम्नलिखित तालिका में दिया गया है : ”

इस बात का अनुमान लगाते हुए कि कोई तालाबन्दी नहीं हुई थी घरेलू उद्योग ने उतना निष्पादन किया होता जैसा कि उसने 2004-05 के दौरान किया था। तथापि, यह अस्वीकार्य है कि तालाबन्दी का प्रभाव केवल तालाबन्दी की अवधि तक ही सीमित रहा है क्योंकि घरेलू उद्योग से सम्पूर्ण आपूर्ति को एकदम ठप्प किए जाने से प्रयोक्ता बाहर जाने के लिए बाध्य हुए और अपनी उत्पादन सुविधाएँ चालू रखने के लिए संबद्ध वस्तु की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु दीर्घावधि आपूर्ति के ठेके निष्पादित किए। अनुरोध है कि घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट स्थिर उत्पादन क्षमता और दीर्घावधिक तालाबन्दी के कारण आई है। अनुरोध है कि संबद्ध वस्तु की माँग में तेजी से वृद्धि हुई है परन्तु घरेलू उद्योग या अन्य भारतीय उत्पादक ने उसकी पूर्ति हेतु क्षमताएँ नहीं बढ़ाई हैं।

(xii) अनुरोध है कि भारत में कुल माँग और भारत में उत्पादन क्षमता के बीच माँग-आपूर्ति के भारी अंतर को देखते हुए भारत से बाहर के देशों से संबद्ध वस्तु के आयात की सतत जरूरत है। इन वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमताएँ स्थिर रही हैं और भारत में किसी भी उत्पादक ने कोई विस्तार नहीं किया है बल्कि इसके विपरीत इसमें नेवेली लिग्नाइट द्वारा संबद्ध वस्तु का उत्पादन न किए जाने तथा याचिकाकर्ता कम्पनी एचओसीएल द्वारा संबद्ध वस्तु का अनुचित दीर्घावधिक स्थगन किए जाने के कारण आगे और गिरावट आई है।

(xiii) पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रयोजन संबद्ध वस्तु के वास्तविक प्रयोक्ताओं/आयातकों पर जुर्माना लगाने या शुल्क की स्वैच्छिक रूप से उच्च दर लगाकर आयातों को अव्यवहार्य बनाने के लिए उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय घरेलू उद्योग को उचित कीमत स्तर उपलब्ध कराना है, भले ही संबद्ध वस्तुएँ पाटन रहित कीमतों पर आ रही हों। जाँच अवधि के बाद संबद्ध देशों से निर्यात कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

103. प्राधिकारी ने उपर्युक्तानुसार प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए अनुरोधों की जाँच की है और यह निष्कर्ष निकाला है कि उठाए गए मुद्दे तथ्यों और आंकड़ों द्वारा समर्थित नहीं है।

104. एसआई ग्रुप को अलग रखने के मुद्दे पर जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना और प्रारंभिक जाँच परिणामों पर कार्यवाही की जा चुकी है और उसे नए सिरे से दोहराने की जरूरत नहीं है।

105. संयंत्र की तालाबंदी और उसके प्रभाव की उचित जाँच की गई है और उसका प्रारंभिक जाँच परिणामों में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।

106. यह आरोप लगाया गया है कि प्राधिकारी ने निष्कर्ष ऐसे निष्कर्ष के कारण रिकार्ड किए बिना दर्ज किए हैं।

107. अनुरोधों में किए गए उल्लेखानुसार डीजीसीआई एंड एस के आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने के कारण एसोसिएशन के लिए इस पहलू पर दलील देने का कोई कारण नहीं है क्योंकि उनके पास इन्हें सार्वजनिक रूप से प्राप्त करने की स्वतंत्रता है।

108. इस बात का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

109. लागत निर्धारण संबंधी सूचना और व्यापार के प्रति संवेदनशील अन्य सूचना, जिसे गोपनीय रहने की अनुमति दी गई है, को आरटीआई के तहत प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

110. इसी प्रकार सीआईएस एलओआर के आंकड़े भुगतान पर प्राप्त किए जाते हैं और प्रयोक्ताओं के पास उन्हें प्राप्त करने की स्वतंत्रता होती है।

111. संक्षेप में ये मुद्दे केवल एक मुद्दा उठाने के लिए उठाए गए हैं और ये प्रमाणित नहीं हैं। गोपनीयता का मुद्दा तथ्यों पर भरोसा किए बिना जोर-शोर से उठाया गया है। एकमात्र यह तथ्य कि घरेलू उद्योग जाँच परिणामों को एक बार जारी किए जाने के बाद ही जागा है, इन जाँच परिणामों के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए उपलब्ध तथ्यों और आंकड़ों पर भरोसा करने के लिए प्राधिकारी के निर्णय में व्यापक सहायता मिली है। मौखिक सुनवाई, प्रकटन विवरण पूर्व एवं प्रकटन विवरण पश्चात के चरणों सहित इस चरण पर भी प्रयोक्ता उद्योग ने ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध कराए बिना एक पाठ के रूप में इन मुद्दों को उठाना चाहा है जिससे प्राधिकारी को पाटन एवं क्षति मार्जिन का निर्धारण करने में मदद मिल सकती थी। प्रयोक्ता उद्योग के पास उन दस्तावेजों/आंकड़ों की पहुँच प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी जिनके बारे में सार्वजनिक रूप में उपलब्ध होने का दावा किया गया है और इसलिए प्राधिकारी पर ऐसे आंकड़ों को गोपनीयता का दर्जा प्रदान करने का आरोप लगाना आधारहीन है। सार्वजनिक फाइल की पहुँच से इनकार करना, उसका समुचित रखरखाव न करना और प्रयोक्ताओं को सुनवाई पश्चात अनुरोध उपलब्ध न कराने की बात से इनकार किया है। प्राधिकारी यह आवश्यक नहीं मानते हैं कि खासकर प्रयोक्ता उद्योग से उचित उत्तर के अभाव में और जो भी उत्तर प्रस्तुत किया गया है वह अस्पष्ट अनुरोधों के रूप में है और वे भी ऐसे समय में किए गए हैं जब जाँच पूर्ण होने के करीब है, आरोपों के लिए अस्पष्ट एवं अवांछित बातों का उत्तर दिया जाए। प्राधिकारी का यह विचार है कि इन प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध जाँच में केवल विलम्ब करने और कार्यवाही में भागीदारी का लाभ उठाने के लिए हैं। एकमात्र तथ्य यह है कि सेंचुरी प्लाइ लेमिनेट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन का एक भाग है और यह एसोसिएशन प्राधिकारी पर सेंचुरी प्लाइ द्वारा किए गए अनुरोधों को उपलब्ध न कराने का आरोप लगा रही है, इस निष्कर्ष का एक स्पष्ट संकेतक है। संक्षेप में प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोध विलम्ब की एक युक्ति के अलावा कुछ नहीं है।

ट.1 पाटित आयातों का कीमत ह्रासकारी तथा न्यूनकारी प्रभाव

112. पाटित आयातों के कीमत ह्रासकारी प्रभाव की जाँच भी उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति और सम्बद्ध देशों से पहुँच मूल्य के संदर्भ में की गई है।

113. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि के दौरान बिक्री लागत में ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति रही थी। बिक्री लागत, जो आधार वर्ष में 100 (सूचीबद्ध) थी, जाँच अवधि में बढ़कर 136.21 हो गई; इसका मुख्य कारण बेजिन तथा एलपीजी जो पेट्रो आधारित उत्पाद हैं की निविष्टि लागत में वृद्धि रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि बिक्री कीमत में वृद्धि 2004-05 तक लागत से अधिक रही थी तत्पश्चात् बिक्री कीमत में वृद्धि लागत में बढ़ोत्तरी के अनुपात में नहीं हुई थी। उत्पादन लागत की प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान उत्पादन की भारत औसत लागत में 36% की वृद्धि हुई जबकि बिक्री कीमत में जाँच अवधि के दौरान केवल 23% की वृद्धि हुई थी जिससे यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप बिक्री कीमत प्राप्त नहीं कर सका।

ट.2 क्षति संबंधी अन्य मानदण्डों की जाँच

114. घरेलू उद्योग की मात्रा एवं कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और आयातों की मात्रा एवं मूल्य, क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग एवं घरेलू उद्योग की बिक्री के साथ-साथ पूर्ववर्ती भाग में विभिन्न खण्डों के बाजार हिस्सों के साथ माँग की पद्धति की जाँच करने के बाद ऐसे अन्य आर्थिक मापदण्डों, जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मौजूदगी का पता चल सकता है, का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है :

ट.3 लाभ एवं नकद प्रवाह पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06	जाँच अवधि
बिक्री की लागत	रु./मी. टन	36851	48871	49093	50196
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	132.62	133.22	136.21
बिक्री कीमत (एनएसआर)	रु./मी. टन	43249	63525	52175	53030
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	146.88	120.64	122.62
लाभ/हानि	रु./मी. टन	6398	14654	3082	2834
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	229.04	48.18	44.29
लाभ/कर पूर्व लाभ	रु./लाख	2404.53	6486.50	867.50	922.25
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	269.76	36.08	38.35
पीबीआईटी	रु./लाख	2647.86	6691.97	1036.49	1095.25
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	252.73	39.14	41.36
नकद लाभ	रु./लाख	2521.03	6594.21	939.28	995.61
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	261.57	37.26	39.49

115. आंकड़ों से यह पता चलता है कि आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की भारत औसत उत्पादन लागत में 36% की वृद्धि हुई जिसकी तुलना में जाँच अवधि के दौरान भारत औसत बिक्री कीमत में केवल 23% की वृद्धि हुई। प्रति इकाई लाभ, जो आधार वर्ष में

100 (सूचीबद्ध) था, में वर्ष 2004-05 में 129% की वृद्धि हुई तथा 2005-06 में घटकर 48% और जाँच अवधि के दौरान 44% हो गया। घरेलू बिक्री पर घरेलू उद्योग का लाभ (पीबीआईटी) जो 2003-04 में 100 (सूचीबद्ध) था, में 2004-05 में 154% की वृद्धि हुई और 2005-06 में घटकर 39% और जाँच अवधि में 41% हो गया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष 2003-04 की तुलना में जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में पर्याप्त विकृति आई है।

ट.4 निवेश पर आय और पूँजी जुटाने की क्षमता.

	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06	जाँच अवधि
पीबीआईटी	रु./लाख	2647.86	6691.97	1036.49	1095.25
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	252.73	39.14	41.36
निवल नियत परिसम्पत्तियाँ	रु./लाख	1476.06	1372.65	1077.23	1132.05
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	92.99	72.98	76.69
कार्यशील पूँजी	रु./लाख	2832.98	4289.04	3444.61	4008.66
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	151.40	121.59	141.50
लगाई गई पूँजी- एनएफए	रु./लाख	4309.04	5661.69	4521.84	5140.71
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	131.39	104.94	119.30
लगाई गई पूँजी पर आय- एनएफए आधार पर	%	61.45	118.20	22.92	21.31
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	192.35	37.30	34.67

116. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई पूँजी पर अर्जित आय के प्रतिशत में लगातार गिरावट आई है। लगाई गई पूँजी पर आय, जो 2003-04 में 100 (सूचीबद्ध) थी, जाँच अवधि में तेजी से घटकर 34.67 हो गई।

ट.5. लाभप्रदता

	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06	जाँच अवधि
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन	207.49	247.91	153.53	180.39
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	119.48	73.99	86.94

117. प्रति कर्मचारी उत्पादन संबंधी आंकड़ों से यह पता चलता है कि उत्पादकता आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान घटकर 87% होने से पूर्व वर्ष 2004-05 में बढ़कर 119% हो गयी थी।

ट.6. रोजगार एवं मजदूरी

	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06	जाँच अवधि
रोजगार (कर्मचारियों की संख्या)	संख्या	193	195	187	190
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	101.04	96.93	98.33
मजदूरी	रु./लाख	140.16	163.78	168.87	173.93
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	116.86	120.49	124.10

118. रोजगार के स्तर में कोई खास परिवर्तन प्रदर्शित नहीं होता है। सूचीबद्ध रूप में यह आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान घटकर 98% हो गया है। आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान मजदूरी में 24% की वृद्धि हुई।

ट.7 मालसूचियाँ

	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06	जाँच अवधि
शुरूआती स्टॉक	मी. टन	688	2924	2214	207
अंतिम स्टॉक	मी. टन	2924	2214	2618	1728
औसत स्टॉक	मी. टन	1806	2569	2416	967
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	142.25	133.76	53.55
बिक्री दिवसों की संख्या के संबंध में औसत स्टॉक	संख्या	18	21	31	11
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	120.77	178.63	61.83

119. औसत मालसूची में प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि औसत मालसूची आधार वर्ष में 100 से घटकर जाँच अवधि में 54 हो गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि की शुरूआत में शुरूआती मालसूची लगभग दो दिन की बिक्री के बराबर थी जो जाँच अवधि की समाप्ति पर बढ़कर लगभग 19 दिन की बिक्री के बराबर हो गई। दूसरे शब्दों में जाँच अवधि के दौरान मालसूची में वृद्धि हुई है क्योंकि अंतिम मालसूची शुरूआती मालसूची की लगभग 8 गुना थी जिससे प्रतिकूल बिक्री का पता चलता है।

ट.8 वृद्धि

120. माँग में वृद्धि में आधार वर्ष से लेकर जाँच अवधि तक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित होती है। उत्पादन एवं बिक्री में वृद्धि 2004-05 में सकारात्मक, 2005-06 में नकारात्मक और जाँच अवधि के दौरान पुनः सकारात्मक हो गई। उत्पादन लागत में वर्ष 2004-05, 2005-06 और जाँच अवधि में बढ़ती हुई प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। बिक्री कीमत की वृद्धि में 2004-05 में वृद्धिकारी और 2005-06 में नकारात्मक तथा जाँच अवधि में सकारात्मक प्रदर्शित होती हैं। लाभों में वृद्धि में 2004-05 में सकारात्मक वृद्धि और 2005-06 में नकारात्मक तथा जाँच अवधि में सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है।

ट.9 निवेश एवं पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता

121. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष से जाँच अवधि तक सम्बद्ध वस्तु की क्षमता में परिवर्तन नहीं किया था। जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने कोई नया निवेश नहीं किया है और उनके अनुरोध के अनुसार आगे निवेश करने की कोई योजना नहीं है।

ट.10 पाटन की मात्रा

122. जिस तक घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से क्षति हो सकती है, उस सीमा के एक संकेतक के रूप में पाटन की मात्रा से यह पता चलता है कि जाँच अवधि के लिए संबद्ध देशों के खिलाफ निर्धारित पाटन मार्जिन पर्याप्त है।

ट.11 कीमता को प्रभावित करने वाले कारक

123. जहाँ तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद के कीमत की तुलना में पाटित आयातों पर कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में अन्यथा पर्याप्त कमी हुई है या ऐसी वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान आयात कीमतों का विश्लेषण किया। यह पाया गया था कि समस्त संबद्ध देशों के संबंध में जाँच अवधि के दौरान प्रति मी. टन पहुँच मूल्य बल्क फेनॉल की बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत दोनों से कम रही थी। यह भी पाया गया था कि जाँच अवधि में प्रति मी. टन आयात का पहुँच मूल्य कोरिया गणराज्य को छोड़कर समस्त संबद्ध देशों से डिब्बाबंद फेनॉल के संबंध में निवल बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत से अधिक है। जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से हुए कुल आयातों में से डिब्बाबंद और बल्क रूप में आयात क्रमशः 5% और 95% हुए हैं। घरेलू बाजार में कीमत को प्रभावित कर सकने वाले कारकों के विश्लेषण हेतु घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धी स्थानापन्न की कीमतों के कारण लागत संरचना में परिवर्तन, यदि कोई हो, की जांच की गई है। जाँच अवधि के दौरान उत्पादन की भारित औसत लागत में 36% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान भारित औसत निवल बिक्री कीमत में केवल 23% की वृद्धि हुई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है जिससे भारतीय बाजार में कीमत कटौती हो रही है। जाँच अवधि के दौरान कीमत कटौती 4-10% के बीच और जाँच अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री 12-17% के बीच रही थी।

ट.12 क्षति संबंधी निष्कर्ष

124. क्षति संबंधी उपर्युक्त मापदण्डों की जाँच से यह पता चलता है कि आधारवर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान माँग में 10% (कैप्टिव बिक्री सहित) वृद्धि हुई थी। माँग में समग्र वृद्धि के बावजूद आधार वर्ष 2003-04 की तुलना में जाँच अवधि के दौरान उत्पादन एवं घरेलू उद्योग की बिक्री घटकर क्रमशः 85% और 87% हो गई। इसी अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात 2003-04 में 13123 मी. टन से पर्याप्ततः बढ़कर जाँच अवधि में 53538 मी. टन के हो गए अर्थात् इनमें 132% की वृद्धि हुई। माँग के संबंध में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा 2003-04 में 17% से बढ़कर जाँच अवधि में 35% हो गया जबकि घरेलू उद्योग की माँग का हिस्सा 27% से घटकर इसी अवधि के दौरान 21% हो गया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में टिक नहीं पाया है। माँग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 100% से घटकर जाँच अवधि में 86% हो गया। इस प्रकार, जाँच अवधि में स्थापित क्षमता अप्रयुक्त बनी रही। आधार वर्ष के 100 की तुलना में जाँच अवधि के दौरान लाभ (पीबीआईटी) घटकर 41 हो गया। आधार वर्ष 2003-04 के 100 की तुलना में जाँच अवधि के दौरान लगाई गई निवल पूँजी पर आय घटकर 21 हो गई।

125. संबद्ध देशों से आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है और इसका कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे कीमत ह्रास और कीमत कटौती हुई है।

126. हितबद्ध पार्टियों ने यह तर्क दिया था कि घरेलू उद्योग ने 2005-06 में संयंत्र की तालाबन्दी का सामना किया। घरेलू उद्योग ने इस बात का अनुमान लगाते हुए कि उसने तालाबन्दी के दौरान

उसी दर पर उत्पादन किया होता जैसा कि उसने 2005-06 में उत्पादन किया था और समस्त उत्पादन की बिक्री की थी, विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध कराया है जो निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06 समायोजित	जाँच अवधि
स्थापित क्षमता	मी. टन	40000	40000	40000	40000
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	मी. टन	40094	48403	34348	34275
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	86	85
क्षमता उपयोग (%)	%	100.24	121.01	85.87	85.69
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	86	85
घरेलू बिक्री	मी. टन	37583	44265	33737	32548
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	90	87
उत्पादन की लागत	रु./मी.टन	36851	48871	48421	50196
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	132.62	131.40	136.21
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	43249	63525	52175	53030
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	121	123
लाभ/हानि	रु./मी.टन	6398	14654	3754	2834
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	229	59	44
लाभ/हानि	रु./लाख	2404.53	6486.50	1266.49	922.25
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	270	53	38
पीबीआईटी	रु./लाख	2647.86	6691.97	1435.48	1095.25
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	253	54	41
नकद लाभ	रु./लाख	2521.03	6594.21	1338.28	995.61
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	262	53	39
आरओसीई	%	61.45	118.20	31.75	21.31
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	192	52	35
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन	207	248	183	180
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	88	87
संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	23123	17427	49997	53538
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	216	232
अन्य देशों से आयात	मी. टन	42302	47607	37850	38040
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	89	90
कुल आयात	मी. टन	65425	65034	87847	91578
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	134	140
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	37583	44265	33737	32548
अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी. टन	35090	35410	28475	28289
कुल माँग	मी. टन	138098	144710	150059	152415
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	109	110
माँग में बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	27.21	30.59	22.48	21.35
अन्य उत्पादक	%	25.41	24.47	18.98	18.56

संबद्ध देश	%	16.74	12.04	33.32	35.13
अन्य देश	%	30.63	32.90	25.22	24.96

127. उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उत्पादन, बिक्री मात्रा, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, कीमत प्रभावित करने वाले कारकों, लाभ, निवेश पर आय, नकद लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन विकृत हुआ है और इस प्रकार सामूहिक एवं संचयी रूप से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ट.13 कारणात्मक संबंध

128. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के कारण के संबंध में अपने निष्कर्ष निकालने के लिए और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.5 के अनुसार तथा यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत नियम 11 के तहत अनुबंध II के पैरा (V) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सभी ज्ञात कारकों के प्रभाव और घरेलू उद्योग की स्थिति पर उनके परिणामों की जाँच की। पाटित आयातों से भिन्न ज्ञात कारकों, जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकते हैं, की भी जाँच की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन अन्य कारणों से हुई सम्भावित क्षति पाटित आयातों के कारण नहीं हुई थी।¹ सम्बद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि (समग्र रूप में और माँग में हिस्से, दोनों के संबंध में) के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पर्याप्त गिरावट आई है। संबद्ध देशों, के बाजार हिस्से में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आई गिरावट से घरेलू उद्योग बाजार में माँग में हुई वृद्धि के अनुरूप अपनी बिक्री बढ़ाने से वंचित हुआ। इसके विपरीत आधार वर्ष 2003-04 की तुलना में जाँच अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्री दोनों में गिरावट आई थी। परिणामतः घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का ईष्टतम उपयोग नहीं कर सका क्योंकि जाँच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग केवल 86% था। परिणामतः घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में वृद्धि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट के परिणामस्वरूप नहीं हो सकी।

129. आयातों द्वारा की गई पर्याप्त कीमत कटौती से घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि की सीमा तक अपनी कीमत बढ़ाने से वंचित हुआ। परिणामस्वरूप निरंतर सुधार प्रदर्शित किए जाने के बाद जाँच अवधि के दौरान लाभ/नकद प्रवाह एवं निवेश पर आय में कमी आई। यद्यपि घरेलू उद्योग वर्ष 2003-04 और 2004-05 में कीमत में वृद्धि करने में समर्थ रहा था तथापि, पाटित आयातों के कारण उसका निष्पादन विकृत हो गया जिससे वह कीमत में विधिसम्मत बढ़ोत्तरी करने से वंचित हुआ।

130. इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ठ. अन्य ज्ञात कारकों की जाँच

ठ.1 अन्य स्रोतों से हुए आयातों की मात्रा एवं कीमत

131. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुल आयातों में से जाँच अवधि के दौरान अन्य देशों से हुए आयातों की मात्रा 42% है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों से हुए आयातों द्वारा भी घरेलू

उद्योग को क्षति पहुँचाने में योगदान मिल रहा है। यह नोट किया गया है कि अन्य देशों से हुए आयातों पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लग रहा है।

ठ.2. माँग में कमी और/अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन

132. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि के दौरान समग्र माँग में कोई कमी नहीं हुई है। इसके विपरीत सम्बद्ध वस्तु की समग्र माँग में जाँच अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है। आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तु की कुल माँग में 10% (कैप्टिव बिक्री सहित) की वृद्धि प्रदर्शित हुई है। घरेलू बाजार में उत्पाद की खपत की पद्धति में भी ऐसा कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है जिसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण माना जा सके।

ठ.3. विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

133. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सम्बद्ध वस्तु का एकमात्र बाजार है जहाँ सम्बद्ध देशों से पाटित आयात घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु से सीधी प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आयातित उत्पाद की बिक्री घरेलू रूप से उत्पादित सम्बद्ध वस्तु के रूप में एक समान वाणिज्यिक ग्रेडों और विनिर्देशनों की पूर्ति हेतु किया जाता है और यह कि आयातित सम्बद्ध वस्तु तथा घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु समान वस्तुएँ हैं और इनका उपयोग एक समान अनुप्रयोगों/अंतिम प्रयोगों में किया जाता है।

134. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उद्योग में प्रचलित ऐसा कोई प्रतिबंधात्मक व्यवहार नहीं है जिसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण माना जा सके।

ठ.4 प्रौद्योगिक विकास

135. याचिकाकर्ता के रिकॉर्डों की जाँच के आधार पर प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि प्रौद्योगिक विकास घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एक संगत कारक नहीं रहा है।

ठ.5 निर्यात निष्पादन

136. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निर्यात मात्रा नगण्य रही है। विभिन्न आर्थिक संकेतकों के संबंध में निष्पादन का निर्धारण केवल घरेलू बिक्री के बारे में किया गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी का यह मानने का प्रस्ताव है कि घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के परिणामस्वरूप नहीं हो सकती है।

ठ.6 घरेलू उद्योग की उत्पादकता

137. आधार वर्ष 2003-04 की तुलना में जाँच अवधि के दौरान इसी अवधि में कुल उत्पादन में आई गिरावट के कारण प्रति कर्मचारी उत्पादन के सम्बन्ध में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट प्रदर्शित हुई है।

138. प्राधिकारी की जानकारी में ऐसा कोई अन्य कारक नहीं लाया गया है जिससे घरेलू उद्योग को संभावित क्षति पहुँच सकती हो।

ड. कारणात्मकता संबंधी निष्कर्ष

139. पाटित आयातों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में अत्यधिक गिरावट आई है। आगे यह देखा जाता है कि सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आई गिरावट से घरेलू उद्योग माँग में वृद्धि के अनुरूप अपनी बिक्री बढ़ाने से वंचित हुआ। इसके परिणामस्वरूप जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में उतनी सीमा तक वृद्धि नहीं हुई जितना कि घरेलू उद्योग द्वारा अपनी क्षमता के इष्टतम उपयोग द्वारा की जा सकती थी। पाटित आयातों द्वारा कीमत में की गई पर्याप्त कटौती से घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि की सीमा तक अपनी कीमतें बढ़ाने से वंचित हुआ। परिणामतः जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर आय में गिरावट आई। कीमत में अत्यधिक कटौती और पाटित आयातों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि से लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर आय के सम्बन्ध में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन मापदण्डों में 2004-05 तक सुधार होने के बाद जाँच अवधि में गिरावट आई।

140. अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.5 के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों के मूल के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ड. क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

141. प्राधिकारी द्वारा क्षति रहित कीमत की तुलना क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु आयातों के पहुँच मूल्य के साथ की गई है। प्रत्येक सम्बद्ध देश से आयातों की भारित औसत पहुँच कीमत तथा क्षति मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है :

अम. डालर/मी. टन

कम्पनी का नाम	क्षति मार्जिन (बल्क)	क्षति मार्जिन (डिब्बाबंद)	क्षति मार्जिन (भारित औसत)	क्षति मार्जिन (%)
कोरिया गणराज्य के निर्यातक	196	198	196	15.29%
ताईवान के निर्यातक	152	-89	137	10.66%
यूएसए के निर्यातक	202	-283	181	14.06%

ण. निष्कर्ष

142. हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए मुद्दों और किए गए अनुरोधों तथा इस जाँच परिणाम में दर्ज किए गए अनुसार प्राधिकारी के संमक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों की जाँच करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :

- (i) सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु ने भारतीय बाजार में प्रवेश निर्यातक देशों के घरेलू बाजारों में उसकी सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय बाजार में उत्पाद का पाटन हुआ है;
- (ii) सम्बद्ध देशों से आयातित सम्बद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन अत्यधिक और न्यूनतम सीमा से अधिक है;
- (iii) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है; और
- (iv) घरेलू उद्योग को यह क्षति सम्बद्ध देशों के मूल की या वहाँ से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के पाटित आयातों द्वारा मात्रात्मक तथा कीमत प्रभाव, दोनों रूप में हुई है।

त. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

143. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से सम्बद्ध देशों से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

थ. सिफारिशें

144. निर्धारित नियमों के अनुसार पाटन, क्षति और पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जाँच शुरू और सम्पन्न करने तथा सम्बद्ध देशों के विरुद्ध सकारात्मक पाटन मार्जिन एवं ऐसे पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की पुष्टि करने के बाद प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए निश्चयात्मक शुल्क लगाना अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं और सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर नीचे निर्धारित प्रपत्र में और तरीके से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

145. प्राधिकारी द्वारा पालन किए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि यूएसए, कोरिया गणराज्य और ताईवान के मूल की या वहाँ से निर्यातित सीमाशुल्क टैस्फि वर्गीकरण अधिनियम, 1975 के अध्याय 27 और 29 के अंतर्गत आने वाली सम्बद्ध वस्तु के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए जिसकी वसूली अनंतिम शुल्क लगाए जाने की तारीख से की जाए। पाटनरोधी शुल्क निम्नलिखित तालिका के कॉलम सं. 8 में उल्लिखित राशि होगी :

शुल्क तालिका

क्र. सं.	टैरिफ मद का उप शीर्ष	वस्तु का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2907.1110 या 2707.9900	फेनॉल	यूएसए	कोई	कोई	कोई	181	मी. टन	अम. डा.
2.	वही	वही	कोरिया गणराज्य एवं ताईवान के अलावा कोई अन्य	यूएसए	कोई	कोई	181	मी. टन	अम. डा.
3	वही	वही	ताईवान	कोई	कोई	कोई	137	मी. टन	अम. डा.
4.	वही	वही	यूएसए एवं कोरिया गणराज्य के अलावा कोई अन्य	ताईवान	कोई	कोई	137	मी. टन	अम. डा.
5.	वही	वही	कोरिया गणराज्य	कोई	कोई	कोई	196	मी. टन	अम. डा.
6.	वही	वही	ताईवान एवं यूएसए के अलावा कोई अन्य	कोरिया गणराज्य	कोई	कोई	196	मी. टन	अम. डा.

146. उपर्युक्त के अध्याधीन दिनांक 29 अगस्त, 2007 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित अनंतिम जांच परिणामों की एतद्वारा पुष्टि की जाती है।

थ. आगे की प्रक्रिया

147. केन्द्रीय सरकार के आदेशों के खिलाफ कोई अपील, जो इस सिफारिश से उत्पन्न हो सकती है, अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

148. प्राधिकारी अधिनियम के संगत उपबंधों और इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार इसमें यथासंस्तुत निश्चयात्मक उपाय की निरंतरता, उपांतरण या समापन की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा कर सकते हैं। प्राधिकारी द्वारा ऐसी किसी समीक्षा के लिए कोई अनुरोध तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय-सीमा के अनुसार किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा दायर न किया गया हो।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th January, 2008

FINAL FINDINGS

Subject : Anti-dumping investigations involving imports of Phenol originating in or exported from USA, Korea-RP and Taiwan.

No. 14/5/2006-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, (hereinafter referred as Rules) 1995 thereof;

1. WHEREAS M/s Hindustan Organic Chemicals Ltd., Mumbai and M/s SI Group-India Ltd., Mumbai (formerly known as Schenectady Herdillia Limited) (hereinafter referred to as the applicants) have jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as this Authority), in accordance with the Act, and the Rules, alleging dumping of Phenol (herein after also referred to as subject goods), originating in or exported from the USA, Korea-RP and Taiwan (herein after also referred to as subject countries) and requested for initiation of an investigations for levy of anti dumping duties on the subject goods.

2. WHEREAS, the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the applicants on behalf of the domestic industry, issued a public notice dated 11th January 2007 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, in accordance with the sub-Rule 5(5) of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which, if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

3. AND WHEREAS, the Designated Authority notified preliminary findings vide notification No. 14/5/2006-DGAD dated 29th August 2007 and recommended imposition of anti-dumping duty concerning imports of subject goods originating in or exported from USA, Korea-RP and Taiwan.

A. PROCEDURE:

4. The procedure described below has been followed:

(i) On 11th January 2007, the Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority) issued a public notice published in The Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti dumping investigation with regard to imports of Phenol originating in or

exported from USA, Korea-RP and Taiwan, (hereinafter referred as subject countries). The Anti dumping proceeding was initiated following an application received from M/s Hindustan Organic Chemicals Ltd., Mumbai and M/s SI Group-India Ltd., Mumbai (formerly known as Schenectady Herdillia Limited) (hereinafter referred as applicant) on behalf of the domestic industry representing a major proportion of the domestic production of said product. The application contained evidence of dumping of the said product from the subject countries and material injury resulting there from, which was considered sufficient to justify the initiation of the proceedings. The Authority while considering the petition excluded M/s SI Group-India Ltd., Mumbai (formerly known as Schenectady Herdillia Limited) as a part of the domestic industry as they had substantial imports during the Period of Investigation.

(ii) The Authority notified the Embassy of USA, Korea-RP and Taiwan in India about the receipt of fully documented application made by the applicant before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.

(iii) According to sub rule (2) of the rule 6 supra, the Authority forwarded copy of the said initiation notification to the known exporters, importers, industry associations, embassy of the subject countries and to the applicant and gave them an opportunity to make their views known in writing.

(iv) According to sub-rule (3) of Rule 6 supra, the Authority provided a copy of non-confidential version the application to all the known exporters in subject countries and Embassy of USA, Korea-RP and Taiwan in India. According Rule 6 supra, the Authority provided a copy of the relevant questionnaire to all the known exporters and Embassy of USA, Korea-RP and Taiwan in India. The Embassy of USA, Korea-RP and Taiwan in New Delhi were also informed about the initiation of investigation and were requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter and questionnaire sent to the exporters and producers were also sent to the respective embassies along with the names and addresses of the known exporters.

(v) The Authority sent questionnaires, to elicit relevant information, to the following known exporters from USA, Korea-RP and Taiwan.

- a) M/s. Deckota Gasification Company
1600 East Interstate Avenue,
PO Box No. 5540, Bismarck Nd 58506-5540, USA.
- b) M/s. Dow Chemical Co.
(979) 238-2011
2301 N Brazosport Blvd
Freeport, Tx 77541, USA.
- c) M/s. Georgia Gulf
Pasadena
3503, Pasadena Freeway
PO Box No. 1959 Zip 77501 Pasadena Texas, USA.

- d) M/s. Shell Chemicals
Deer Park Chemical Plant & Refinery
5900 Highway 225
Deer Park Texas, USA.
- e) M/s. Formas Chemicals & Fibre Corporation
Formosa Plastics Group
201 Tung Hwa North Road
Taipai (Taiwan Roc.)
- f) M/s. Kumho P&B Chemicals Inc.
319, Hwachi- Dong,
Yeosu City, Cholla Nam-Do, Korea RP.

(vi) None of these exporters responded to the questionnaire in response to the above notification,

(vii) A copy of initiation notification along with the importers questionnaire was also sent to the following known importers and users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4).

- 1) M/s. C.J. Shah and Company
105, Bajaj Bhawan
10th Floor, Nariman Point
Mumbai- 400021
- 2) M/s. Haresh Kumar and Company
1212, Maker Chambers
5 Jamnalal Bajaj Road,
Nariman Point Mumbai-400021.
- 3) M/s. PCL Industries
M-105, Connaught Place
New Delhi-110001
- 4) M/s. Kantilal Manilal and Company
16, Princess Street
Mumbai-400003.
- 5) Sonkamal Enterprises
10, Dev Darshan Apartment
Old Nagardas Road Andheri (East)
Mumbai-400 069
- 6) M/s. Khetan Brothers
C-17, Dalia Industrial Area
Off New Link Road,
Opposite Laxmi Industrial Estate
Andheri (West) Mumbai-400 058
- 7) M/s. Shubham Dyes & Chemicals Limited
1/26, Roop Nagar, Delhi-110 007
- 8) Acron Enterprises
Plot No. 218-219/3, G.I.D.C, Naroda, Ahmedabad

- 9) M/s. Naiknavare Chemicals Limited
1, Vidya Bhavan, 121, Keluskar Road
Shivaji Park, Dadar (West) Mumbai (Maharashtra)
- 10) M/s. Paras Dyes & Chemicals 12th Floor, Vijaya Building
17 Barakhamba Road, New Delhi-110001
- 11) M/s. Torrent Pharmaceuticals Limited,
Ashram Road,
Ahmedabad Road 380009 Gujrat
- 12) M/s. United Phosphorus Ltd.
Eadymoney Terrace, 167,
Dr. Annie Basant Road
Worli, Mumbai-400 018
- 13) M/s. Resins & Plastic Ltd.
Cross Rd. B, Mumbai-400093
- 14) M/s. Kailash Polymers
60, Krishna Market,
Kalkaji, New Delhi.
- 15) Centrum Metalics Pvt. Ltd.
6/221, Deodhar Road,
Matunga-400 019 Mumbai
- 16) M/s. Wonder Laminates Pvt. Ltd.
14, Bhasa, Diamond Harbor road, Kolkata.
- 17) M/s. Meghdev Enterprises.
P.K. House, H/H M.J. Library,
Ellisbridg, Ahmedabad
- 18) M/s. Satguru International
204-D, Pocket-12, Jasola Vihar,
Opp. Appolo Hospital, New Delhi.
- 19) M/s. High Polymer Labs Ltd.
803, Vishal Bhavan,
95, Nehru Place, New Delhi.
- 20) M/s. Rainbow colours & Chemicals
14/A, Bhavik Complex
Ghod Dod Rd., Surat, Gujrat
- 21) M/s. M/s. Bleach Marketing Pvt. Ltd.
120, Bleach Chem Compound,
Nr. Chandola, Ahmedabad
- 22) M/s. Karmen International (P) Ltd.
31A/20, NP, Sidco Industrial Estate, Che, Chennai
- 23) M/s. Krishna Antioxidants Pvt. Ltd.
Lopes Maner, I C Colony,
Near Chandra Ho, Mumbai
- 24) M/s. NGP Industries Ltd:
M-13, Punj House, New Delhi
- 25) M/s. Farmson Pharmaceutical Gujrat Ltd. 5th Floor, Commerce Centre,
Sayajigunj, Baroda.

- 26) M/s. India Glycols Ltd.
C-124, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi.
- 27) M/s. Singh Plasticisers and Resins (I) Pvt.
B-316, 3rd Floor,
Somdutt Chamber-1 Bhika, New Delhi
- 28) M/s. National Plywood Industries Ltd.
5, Fancy Lane, 700 001 Kolkata.

(viii) In response to the above notification, none of the importers or users except M/s Century Ply Ltd. (one of the users of subject product), filed a response to the questionnaire in the form and manner prescribed. The information furnished is not reliable for the purpose of taking inputs that may have an impact on these findings. For e.g. in Annexure 2 rate per MT of the subject goods has been worked out as Rs. 22.47 per MT. Therefore none of the information contained in this Questionnaire response has been considered for the purpose of these investigations. Laminate Manufacturers Association submitted arguments post oral hearing, opposing imposition of ADD. That apart, M/S Centuruy Ply, a part of the Laminate Manufacturers Association also submitted arguments post oral hearing, opposing the antidumping duty. Incidentally a representative of Century ply was also present in the oral hearing on behalf of Laminate Manufacturers Association which inter-alia would mean that Century Ply participated in the oral hearing. However, none of these parties have provided any type of information in the form of logistics / statistics to the Authority that would provide the authority a base for determining Dumping or Injury margin, different fro what has been claimed by the petitioner or the one determined by the authority based uopon available information. Instead, they have merely filed their objections, which have been considered to the extent they have been found relevant to the investigation.

(ix) The Authority notified Preliminary findings vide Notification no. 14/5/2006-DGAD dated the 29th August, 2007 and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication.

(x) The Central Govt. imposed the provisional duties vide notification no.105/2007 dated 19.09.2007.

(xi) The Authority held a public hearing on 9th October 2007 to hear the interested parties orally, which was attended by interested parties. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of views expressed orally. Authority in this finding has considered the written submissions thus received from interested parties. The parties were also asked to file rejoinder submissions on views expressed by other interested parties.

(xii) No arguments or submissions were made by other interested parties (other than the domestic industry) before notifying of preliminary findings. However, arguments that arose and have been put forth by various interested parties after the preliminary findings have been dealt in the present finding. Further, the comments by the interested parties on the present disclosure statement have been appropriately dealt in the Final Findings.

(xiii) The Authority kept available non-confidential version of the evidences/submissions presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties.

(xiv) **** In this notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

(xv) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings have been disclosed to known interested parties on 3rd December 2007 and comments received on the same have been considered in present Final Findings.

(xvi) The investigation of dumping covered the period from 1st July 2005 to 30th June 2006 (Also called the period of investigation or POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the period from 1st April 2003 to the end of period of investigation. (Also called Injury period)

(xvii) The Authority conducted on the spot investigation and verified all the information provided by the domestic industry. The cost of the production of the domestic industry was also analysed to work out the cost of the production and the cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles based on the information furnished by the domestic industry so as to ascertain if anti Dumping duty lower than dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic Industry.

(xviii) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years and the period of investigation

(xix) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigations, or has significantly impeded the investigation, the Authority shall record findings on the basis of the facts available.

(xx) The Authority has considered data relating to cost of production and selling price of all interested parties as confidential as it would give competitive advantage to their competitors. The other information has not been considered as

confidential unless the responding party has given sufficient justification for keeping the information as confidential.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLES.

B.1 VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

5. Following issues have been raised by the domestic industry with regard to product under consideration and like article:

- (i) Phenol is an organic chemical classified under chapter 27 and chapter 29 of the customs Tariff Act under the sub-heading 29071110, 27079900 respectively. The domestic industry has submitted that duty should be recommended on both the classification.
- (ii) Phenol produced by the domestic industry and imported from the USA, Korea RP and Taiwan are like product.
- (iii) Phenol is a basic organic chemical, marketed in two grades viz. Crystalline and Hydrated. The two grades are differentiated on the basis of flow characteristics of Phenol. It is marketed in two forms – loose / bulk and packed.
- (iv) There is no difference in Phenol produced by the Indian industry and Phenol exported from the subject countries. Phenol produced by the Indian industry and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics
- (v) Phenol is used in the manufacture of Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Board, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl oxide etc.
- (vi) There is no difference in the Phenol produced by the domestic industry and imported from subject countries. Phenol produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology (followed by most of the producers world over), functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used the two interchangeably. Phenol produced by the petitioners and imported from subject countries is like article.

B.2 VIEWS OF THE IMPORTERS, CONSUMERS, EXPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

6. None of the importers, consumers, exporters and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to product under consideration, and like articles.

B.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

7. The product under consideration is Phenol originating in or exported from USA, Korea-RP and Taiwan. Phenol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The product is marketed in two forms – bulk and packed. Bulk sales are normally in loose form, whereas packed consignments can be of much smaller container loads and generally packed in drums. Phenol is used in Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl

Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl Oxide etc. This product is classified under Customs Tariff heading no. 2907.11 and 2707.99 as per Indian Trade Classification. The Customs and ITC HS classifications are, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation

8. Rule 2(d) of the Anti-dumping Rule specifies that like articles mean an article, which is identical and alike in all respects to the product under investigation or in the absence of such an article, another article having characteristics closely resembling those of the articles under examination.

9. The petitioner claimed that the goods produced by him are like articles to the goods originating in or exported from subject countries. No other interested party has raised any objection to the claim of the Domestic Industry on this issue. In view of the above the Authority holds that phenol produced by the domestic industry and the one being imported from the subject countries as like articles within the meaning of the rules.

C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

C.1 VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

10. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing of the domestic industry.

(i) The petition was jointly filed by M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd. and SI Group (formerly known as Schenectady Herdillia Ltd.). There are three companies in India who created capacity for production of Phenol namely Hindustan Organic Chemicals Ltd., SI Group (formerly known as Schenectady Herdillia Ltd and Neyveli Lignite. However Neyveli Lignite has not produced/sold phenol in the last three years, as per the annual report of the company. The petitioners, therefore, constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules, 1995.

(ii) Production of petitioner constitutes a major proportion in Indian Production and therefore petitioner should be treated as "domestic industry" within the meaning of the Rules.

C.2 VIEWS OF THE EXPORTER, IMPORTERS, CONSUMERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

11. The Authority notes that none of the producers of the subject goods in Korea-RP, Taiwan or USA has responded to the Designated Authority. However M/S Century Ply Ltd., one of the users of the subject goods has raised certain objections as under;

C.2.1 Century Ply Ltd.

12. The authority is required to examine the performance of SI.Herdilia.

13. S.I. Herdilia has also imported subject goods and huge demand-supply gap has been overlooked by the Authority while recommending Preliminary Findings.

14. S.I. Herdilia has lower cost of production compared to HOCL.

C.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

15. The Authority has examined the contention made by this user in this regard as well as the evidence available on record. With regard to standing of the domestic industry, Rule 2(b) states as under:

"Domestic Industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry

16. Authority notes that one petitioner SI Group (formerly known as Schenectady Herdillia Ltd.) has imported the subject goods during the POI from the subject countries. It is noted that the imports made by the company are in duty free category and in duty paid category, both substantial in volume. In view of the facts & circumstances of the present case, the Authority has considered it appropriate to exclude SI Group from the scope of Domestic Industry.

17. The petitioners were directed to provide injury information after excluding SI Group, which was provided by them. This information was sent to other interested parties participating in the investigations and they were advised to file their comments, if any, on the revised injury information.

18. There are three companies in India who created capacity for production of Phenol namely Hindustan Organic Chemicals Ltd., SI Group (formerly known as Schenectady Herdillia Ltd and Neyveli Lignite. It was however seen from annual reports of Neyveli Lignite that the company has not produced product under consideration in the period of investigation. Authority has considered it appropriate to exclude SI Group from the scope of Domestic Industry as detailed in para 16 and 17 above. M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited, therefore, accounts for a major proportion in Indian production and constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.

19. It has been argued about imports having been made by SI Group. The Authority however notes that the fact of SI Group being an importer is relevant in determining scope of the domestic industry. While petitioners have argued for inclusion of SI Group within the scope of domestic industry, these interested parties have not argued that SI Group should be included within the scope of the domestic industry. The Authority has already excluded SI Group from the scope of the domestic industry.

D. OTHER ISSUES

D.1 VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

20. Given the nature of product and the volatility in the input for the production, the benchmark form of duty is not an appropriate form of duty.

21. The Designated Authority, as a special case, had granted two weeks time to Laminates Association and its members to provide relevant information to the Designated

Authority. However, no information has been provided either by the association or by the laminate manufacturers. On this account alone, their objection must be rejected.

D.2 VIEWS OF THE EXPORTER, IMPORTERS, CONSUMERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

22. The Authority notes that none of the producers of the subject goods in Korea-RP, Taiwan or USA has responded to the Designated Authority.

D.2.1. Century Ply Ltd. and Laminate Manufacturers Association

23. The domestic industry has not disclosed any information about 'long term' plant shut down in their petition for imposition of anti-dumping duty. The authority has not examined the impact of shut down before initiation of the investigation. The exact period of shut down has also not been disclosed even in the Preliminary Findings. Before shut down of production, the performance of D.I. for 2004-05 has shown remarkable results in spite of imports from subject countries.

24. In spite of huge gap in demand and supply Domestic Industry is exporting the subject goods and the export by D.I. and its effect of user industry do not bear a mention in the Preliminary Findings.

25. The Domestic Industry intentionally did not disclose names of major users of Phenol in India to avoid any kind of opposition.

26. Information with regard to imports made by SI Group has not been disclosed. Petitioners have claimed excessive confidentiality on all the issues.

27. The petition filed does not appear to have been examined to ensure that the same justified initiation.

28. The petition filed is not complete as of sections of application as the Performa have not been fully answered, nor necessary evidence has been provided.

29. Domestic industry has been referred to the BIFR prior to the period of investigation. As the Authority may be aware that the reason for referring the matter to the BIFR is the fact that there has been a complete erosion of funds i.e., the accumulated losses exceeded the shareholders funds. We understand that domestic industry was registered as a sick industrial company by the BIFR as per provisions of SICA, vide Case No.501/2005. The Authority may please call for all the documents/submissions relating to the BIFR case including the order passed by the Board. In this connection, kind attention is invited to the Annual Report of 2004-05 of HOCL, the relevant excerpts of which are as follows:

"Your company had been incurring losses from the financial year 1997-98 to 2003-04 and was referred to BIFR as a sick unit after erosion of Net Worth at the end of the financial year 2003-04."

30. The fact that the company has been referred to BIFR makes it clear that the poor performance of the company is on account of their inherent difficulties, which have been

acknowledged in several reports of the government. It is also important to note that even the BIFR application was made prior to the application for anti-dumping on phenol. Under the circumstances, it is apparent that the problems cannot be attributed to the alleged dumping from the subject countries.

31. The petition is deficient in many respects. Adequacy and accuracy of the evidence has not been examined by the Authority. Authority should not have initiated investigations based on such deficient petition.

32. The injury information in the petition is not consistent with the Trade Notice issued by the Authority. The petition should have contained data for one more preceding year.

33. There was no justification for issuance of preliminary findings.

34. The Authority has not disclosed the methodology followed for the determination of non-injurious price and calculations of injury margin.

35. Sudden shut down of M/s. HOCL plant for no plausible reasons, thus creating huge demand/supply gap to the tune of two and a half times of the total Indian capacity (the demands standing at 152415 M.T. with only 40,000 M.T. capacity of Domestic Industry. Domestic industry could not meet the demand in the country.

36. Claim of non-availability of raw material to be a reason for shut down is fanciful and SI Herdilia, supporter of the present petition has been regularly sourcing raw material from international market and has not faced any constrained in terms of availability of raw material.

37. The domestic industry deliberately chose July 05 to June 06 as POI to project increased importation and decline in production to show the same as injury due to importation. Wrong period of investigation has been chosen.

38. The petition filed by Domestic Industry is a blatant example of abuse of process of law and legitimate trade remedy measures for own objectives of Petitioner Company for creating monopolistic situation in the domestic market for their own private profits at the expenses of entire user industry which is not only facing shortage of supply of Phenol in India but also has to face abrupt behavior of domestic producers who refuses to supply the requisite quantities whenever an order is placed upon them.

39. Authority should disclose the price undercutting individually for each of such country.

40. Authority has not disclosed landed value of imports for previous years in the Preliminary Findings to enable them to compare the price trends of previous years.

41. The Authority has erred in overlooking interests of consumer industry and Rule 6(5) of Anti Dumping Rules has not been followed as arguments submitted by the industrial users regarding their plights has not been examined in the Preliminary Findings.

42. Investigations should be terminated in accordance with the Rules 14 of Anti Dumping Rules as Domestic Industry has concealed vital facts from the Designated Authority, which have direct bearing on the case and presented staged injury.

D.2.2 EXAMINATION BY THE AUTHORITY:

43. Information related to long term plant shut down of domestic industry has been disclosed in 2005-06 annual report, which was available to interested parties for inspection and comments.

44. The export volume of the domestic industry is insignificant during POI. Therefore, exports could not have affected overall performance of the domestic industry.

45. The notice of initiation was issued in the Gazette and all parties were expected to be aware of the same. Moreover a copy of the same was also sent to leading Trade Associations including Assocham, FICCCI, CII, as also publishing houses Like Excise Law Times.

46. Imports by SI – Authority have excluded SI from the scope of the domestic industry and therefore any argument with regard to imports by SI is not relevant.

47. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

48. The information provided by the applicant showed sufficient prima facie justification to initiate investigation. On being satisfied, the Authority issued a public notice dated 11th January 2007, initiating antidumping investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from USA, Korea RP and Taiwan.

49. The petition filed by the domestic industry was examined in accordance with requirements under Rule 5 and the investigations were initiated only after satisfying with regard to adequacy and accuracy of the evidence contained in the petition.

50. The Authority notes that the status of the domestic industry is well within the knowledge and there is no suppression of information by the company in this regard. The issue has been examined earlier also by the Authority during the course of investigation relating to Acetone also, wherein the Authority has noted as follows -

" The Authority has examined the issue of HOCL under the BIFR and noted that the reason cited by the applicant before the BIFR was that "the sales at Kochi unit of the company which in fact is profit making unit suffered in 2001-02 due to dumping of products by overseas manufacturers causing severe squeeze in the margins resulting in losses. The Authority further notes that Kochi unit of the company, which basically manufactures phenol and acetone, was making profits during 2002-06, however, the profit was considerably reduced during 2005-06. The Authority also notes that Rasayani unit of the company was making losses during 2000-06. The Authority, therefore, holds that mere registration of unit under SICA would not make it ineligible to seek relief under Anti-dumping Investigations, particularly, when the relevant unit of the company was not suffering losses because of any other reasons."

51. Trade Notice requires injury information for the dumping period of investigation and three preceding years. Information for this period was contained in the petition and has been considered, examined and relied upon for injury determination.

52. The Authority has issued preliminary findings having satisfied itself with regard to the need for the same.

53. The Authority has followed the consistent practice with regard to determination of non-injurious price and injury margin. Methodology followed for non-injurious price determination is being separately disclosed in the disclosure. Injury margin has been determined as the difference between non-injurious price and landed price of imports.

54. The Authority notes that the purpose of anti dumping duties is not to prevent imports into the Country, but to restrict import at dumping prices. Imposition of anti dumping duties would not restrict availability of the product in the country.

55. The Authority notes that the reason for shut down has been mentioned in the annual report of 2005-06 of the company. Merely because other Indian producer did not face raw materials difficulties during this period, does not imply that HOCL (D.I) could not have faced such difficulty.

56. The Authority considers that fixation of the present POI has not in any manner vitiated the present determination because of shutdown faced by HOCL in 2005-06. Details to this effect have already been elaborately described in Para 31 of the Preliminary Findings. In fact, during POI there was no internal factor which would act as a constraint to operate the plant at full capacity, except adverse market conditions.

57. Authority notes that the present investigation is against dumping of the product causing injury to the domestic industry. Injury to the domestic industry is determined considering, inter-alia, profit earned by the domestic industry during the injury period. It cannot therefore be said the impact of imposition of ADD is to permit domestic industry to earn abnormal profits, particularly when India is following "lesser duty rule" where the quantum of ADD is restricted to injury margin.

58. The price undercutting has been determined in the disclosure statement separately for each country, as demanded by interested parties. Further, landed price of imports has also been appropriately determined and disclosed.

59. The Authority has provided sufficient opportunity to the interested parties as required under rule 6 (5). The fact is that these parties have failed to provide any information, except arguments opposing imposition of ADD.

E. De Minimis Import Volumes

60. As per the import data received by the Authority from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), the imports of the subject goods from each of the subject countries are above the de minimis level.

F. DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

61. The Authority notes that Rule 6.8 of the antidumping Rules provide that in a case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary

information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it.

62. Article 6.8 of the Agreement, read with paragraph 1 of Annex II, provides that as soon as possible after the initiation of the investigation, the investigating authorities should specify in detail the information required from any interested party, and the manner in which that information should be structured by the interested party in its response. The authorities should also ensure that the party is aware that if information is not supplied within a reasonable time, the authorities will be free to make determinations on the basis of the facts available, including those contained in the application for the initiation of the investigation by the domestic industry.

63. The Authority notes that the exporters and the governments of the subject countries have been adequately notified about the requirement of submission of information in the form and manner prescribed and adequate opportunity was also granted to the parties to make their submissions in this regard. Therefore, in the absence of cooperation from the subject country, the Authority has determined the dumping margins in respect of the subject country on the basis of facts available.

G. Normal Value and Export Price

G.1 Korea-RP

G.1.1 Normal Value for Korea-RP

64. No exporter has responded to the initiation notification and submitted any information. In absence of any data, the Authority has relied upon the facts available as per Rule 6(8) of the Anti-dumping Rules, to determine the normal value. The normal value has been constructed on the basis of facts available. For constructing normal value, the price of Benzene has been taken from the data of DGCIS and for Propylene from ICIS LOR Asia. The consumption norms of the domestic industry and also standard input output norms (SION) have been relied upon. For utilities, consumption norm and prices of the domestic industry has been taken, except for power. For power, the rate has been taken as per the available information of power rate in the exporting country. Conversion cost which includes labour, depreciation and manufacturing expenses have been taken as per domestic industry. SGA, including interest, has been taken as per domestic industry. The profit margin @ **** has been considered on the cost of production. By adopting this methodology, the constructed normal value for bulk phenol has been calculated as US\$ ****PMT. For packed material, the cost of packing material of the domestic industry has been added to calculate the normal value. By this method the normal value for packed phenol has been calculated as US\$ **** PMT.

G.1.2. Export price for Non-cooperating Exporters

65. The data reported by the DGCI&S for exports from Korea-RP has been relied upon to calculate the ex-factory export price. The DGCIS data shows import of both bulk and packed material during the POI. Adjustment on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight, port expenses, bank charges, and credit cost have been made to arrive at the ex-factory export price. By adopting the above method, the ex-factory export price has been calculated as US\$ **** PMT for bulk material. For packed material, the ex-factory export price calculated as US\$ **** PMT.

G.2. Taiwan**G.2.1. Normal Value for Taiwan**

66. No exporter from the Taiwan has responded to the Initiation Notification. In absence of any response, the Authority has relied on the facts available as per Rule 6(8) of the Anti-dumping Rules to determine the normal value. For constructing normal value, the price of Benzene has been taken from the data of DGCIS and for Propylene it has been taken from ICIS LOR Asia. The consumption norms of the domestic industry and SION have been relied upon. For utilities, consumption norm and prices of the domestic industry have been taken except for power for which the rate has been taken as per the available information of power rate in the exporting country. Conversion cost has been taken as per the domestic industry. SGA including interest has been taken as per domestic industry. The profit margin @ **** has been considered on the cost of production. By adopting this methodology, the constructed normal value for bulk phenol has been calculated as US\$****MT. For packed material, the cost of packing material of the domestic industry has been added to calculate the normal value. By this method the normal value for packed phenol has been calculated as US\$**** PMT.

G.2.2. Export price for Non-cooperating Exporters

67. The data reported by the DGCI&S for exports from Taiwan has been relied upon to calculate the ex-factory export price. The DGCIS data shows export of both bulk and packed material during the POI. Adjustment on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight, port expenses, bank charges, and credit cost have been made to arrive at the ex-factory export price. By adopting the above method, the ex-factory export price has been calculated as US\$ **** PMT for bulk material. For packed material, the ex-factory export price calculated as US\$ **** PMT.

G.3. USA**G.3.1. Normal Value for USA**

68. No exporter from USA has responded to the initiation notification and submitted any information. In absence of any data, the Authority has relied on the facts available as per Rule 6(8) of the Anti-dumping Rules to determine the normal value. For this purpose, average price for Benzene and Propylene reported in ICIS LOR (US Gulf) for the period of investigation has been taken as normal value. The consumption norms of the domestic industry and SION have been relied upon. For utilities, consumption norms and prices of domestic industry during POI have been considered, except for power, for which the rate has been taken as per the available information regarding power rate in the exporting country. The conversion cost has been taken as per the domestic industry. SGA, including interest has been taken as per domestic industry. The profit margin of **** has been considered on the cost of production. By adopting this methodology, the constructed normal value for bulk phenol has been calculated as US\$**** PMT. For packed material, the cost of packing material of the domestic industry has been added to calculate the normal value. By this method the normal value for packed phenol has been calculated as US\$ ****MT.

G.3.2. Export price for Non-cooperating Exporters

69. The data reported by the DGCIS for exports from USA has been relied upon to calculate the ex-factory export price. The DGCIS data shows export of both bulk and packed material during the POI. Adjustment on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight, port expenses, bank charges and credit cost have been made to arrive at the ex-factory export price. By adopting the above method, the ex-factory export price has been calculated as US\$ **** PMT for bulk material. For packed material, the ex-factory export price calculated as US\$ **** PMT.

H. Dumping Margin

70. On the basis of normal values and export prices as determined above, the dumping margins for exporters are determined as per table below. As already detailed no exporter response was received and therefore all the exporters from subject countries have been treated as non-cooperating exporters:-

IN US\$ (PMT)							
Exporter/Producer From	Normal Value-Bulk	Normal Value-Packed	Export Price-Bulk	Export Price-Packed	Dumping Margin - Bulk	Dumping Margin - Packed	Weighted Dumping Margin -
Korea-RP	***	***	***	***	***	***	27.28%
Taiwan	***	***	***	***	***	***	21.20%
USA	***	***	***	***	***	***	33.45%

71. The dumping margins so determined are significant and above de-minimis-level.

I. INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF CAUSAL LINKS**I.1. Views of the domestic industry**

72. The followings are the views of domestic industry:-

- a) Export price from the subject countries has remained at dumped level during POI. Further, these prices have not increased proportionate to increase in input prices from base period to POI.
- b) Production, sales volumes and capacity utilization of the domestic industry declined after showing improvements in 2004-05.
- c) Profit/Loss (PBT, PBIT and PBDIT) of the domestic industry have all shown significant decline after improvement up to 2004-05.
- d) Market share of the domestic industry declined. This is due to the fact that dumped imports have captured significant market share of demand in India.
- e) Import from each of the subject countries has been undercutting the prices of the domestic industry to a significant degree.
- f) Imports from the subject countries has forced the domestic industry to reduce the price steeply during 2005-06 and proposed investigation period. Thus, the imports were depressing the prices in this period.

- g) Employment levels with the domestic industry have not undergone any significant change.
- h) Salary & wages: - Salary and wages with the domestic industry increased.
- i) Demand and market share: - Whereas the market shares of the imports have increased, that of the domestic industry has declined.
- j) Growth:- Growth of the domestic industry in a number of parameters shows negative trend.
- k) Domestic industry has suffered material injury and is trapped in a vicious cycle of volume effect and price effect. With increase in volume of imports of the subject good from the subject countries into the Indian market as a result of excess capacity with the Foreign Producers, the domestic industry suffered from loss of sale and loss of market share. This resulted in adverse volume effect. Loss of sale forced the domestic industry to reduce their domestic selling price in order to sell the subject good in the domestic market thus resulting in adverse price effect. The exporters further reduced the selling price and as a result, the domestic industry reduced the selling price further and the process continued. Resultantly, domestic Industry faced adverse volume effect and adverse price effect as a result of unfair trade practices of the exporting countries.
- l) Imports from subject countries are adding to the material injury, already being suffered by the domestic industry.
- m) There is significant increase in the import volumes in absolute terms. This increase in imports is in spite of best efforts of the domestic industry to sell their material even at sub-optimal prices. The increase in imports would have been more, had the domestic industry not made efforts to curtail the same by offering lower prices.
- n) Price undercutting is significant. In spite of offering matching prices, there is a positive price difference between the domestic product and imported product. Given nature of the product involved, any price difference between the domestic product and imported product is not acceptable to the consumers and the domestic industry is under constant pressure for price reductions. Domestic industry cannot afford to sell at prices, significantly higher than the imported prices. The only option with the domestic industry is to sell at matching prices. Even a small price difference is in fact huge in this kind of product.
- o) Petitioners conducted extensive analysis of exports from subject countries to world over in terms of its likely impact on the domestic industry. World exports of subject countries are showing increasing trends, clearly implying surplus unutilized capacities with the Foreign Producers which are likely to be offloaded to India at dumped prices.

I.2. Examination by the Authority

I.2.1 Cumulative assessment of injury

73. As per annexure-II (iii) of the Rules, in case, imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to Anti-dumping investigation, the Authority is required to cumulatively assess effect of such imports, only when it determines that

- (a) The margin of dumping established in relation to imports from each country is more than 2% expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is 3% and cumulatively account for more than 7% of the imports of like article, and,
- (b) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic article.

74. The Authority has found that the margin of dumping in respect of each of the subject country is more than 2% and the volume of imports from each country is also more than 3%.

75. With a view to assess the conditions of competition between imported products and the like domestic product, the Authority notes that -

- i) The subject goods have been imported from the subject countries under the same tariff classification;
- ii) The Authority has found that the imported subject goods are commercial substitutes of the domestically produced Phenol.
- iii) The information furnished to the Authority gives a reasonable indication that the exports made from the subject countries compete in the same market, as these are like products.

76. Therefore, the Authority notes that it is appropriate to, cumulatively assess the effect of imports of the subject goods on the domestically produced like article, in the light of conditions of competition between the imported products and the like domestic product.

77. The Authority has taken note of various arguments put forth by the Domestic Industry (There was no response from other interested parties).

78. Annexure II of the AD Rules requires that determination of injury shall involve an objective examination of both:

- (a) The volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products; and
- (b). Consequent impact of these imports on domestic producers of such Products.

79. The Authority while examining the volume of dumped imports is required to examine whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a

significant degree, or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.

80. For the purpose of injury analysis the Authority has examined cumulative effect of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on all relevant Economic factors and indices having a bearing on the state of industry to evaluate the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.

81. Since significant dumping margins have been established for the exports from the subject countries, entire exports from the subject countries have been treated as dumped imports for the purpose of injury analysis and causal link examination.

I.2.2 Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry

82. The Authority collected transaction wise details of imports of subject goods from DGCI&S. As per the data, cumulative imports from subject countries have increased significantly in absolute terms and in relation to imports in India. Imports from Korea-RP, Taiwan and USA constitute 10.66%, 27.21% and 20.59% respectively in the POI. The imports from subject countries are more than de-minimis individually. The Authority notes that although the share of imports from USA has been on decline in POI compared to period of injury, (Down to 20.59% in POI as against 35.34% in 2003-04) the share of subject countries in imports, which was 35.34% in 2003-04 increased to 58.46% in POI.

I.2.2.1 Import Volumes and share of subject country

	Units	2003-04	2004-05	2005-06	POI
Korea RP	MT	0	32	7017	9765
Taiwan	MT	0	1985	24743	24920
USA	MT	23123	15410	23832	18853
Subject Countries	MT	23123	17427	55591	53538
Trend	Indexed	100	75	240	232
Other countries	MT	42302	47607	37850	38040
Trend	Indexed	100	113	89	90
Total Imports	MT	65425	65034	93441	91578
Trend	Indexed	100.00	99.40	142.82	140

I.2.2.2. Market share in imports

Korea RP	%	0	0.05	7.51	10.66
Taiwan	%	0	3.05	26.48	27.21
USA	%	35.34	23.70	25.50	20.59
Subject Countries	%	35.34	26.80	59.49	58.46
Trend	Indexed	100.00	75.82	168.33	165.42

Other countries	%	64.66	73.20	40.51	41.54
Trend	Indexed	100.00	113.22	62.65	64.24
Production of DI	MT	40094	48403	28754	34275
Imports from subject countries	MT	23123	17427	55591	53538
Imports from subject countries as a percentage of production of DI	%	57.67	36	193.34	156.20

I.3 Demand, Output and Market shares

I.3.1 Growth In Demand

I.3.1.1 Growth in Demand including Captive Consumption

	Unit	2003-04	2004-05	2005-06	POI
Domestic Industry	Mt	37583	44265	28143	32548
Other Producers	Mt	35090	35410	28475	28289
Total Import	Mt	65425	65034	93441	91578
Total Demand	Mt	138098	144710	150059	152415
Trend	Indexed	100.00	104.79	108.66	110.36

I.3.1.2 Growth in Demand excluding Captive Consumption

	Unit	2003-04	2004-05	2005-06	POI
Domestic Industry	Mt	37583	44265	28143	32548
Other Producers	Mt	32329	34099	26952	26561
Total Import	Mt	65425	65034	93441	91578
Total Demand	Mt	135337	143399	148536	150687
Trend	Indexed	100.00	105.96	109.75	111.34

83. Demand of subject goods has been determined by addition of domestic sales (including captive sales) of domestic industry and all imports from all countries. The Authority notes that demand for the subject goods had been growing from base year to POI. It grew by 10% during POI as compared to base year i.e. 2003-04.

84. The growth in demand of subject goods excluding captive sales also shows similar trends. As compared to base year it grew by 11%.

85. Imports from subject countries show a growing trend in relation to production of the domestic industry. The imports from subject countries was only 58% in relation to the production of the domestic industry in the base year 2003-04, which has gone up in percentage terms to 156.20% in POI.

I.4 Capacity, production and capacity utilization of the Domestic Industry

	Unit	2003-04	2004-05	2005-06	POI
Installed Capacity	Mt	40000	40000	40000	40000
Trend	Indexed	100.00	100.00	100.00	100.00
Production	Mt	40094	48403	28754	34275
Trend	Indexed	100.00	120.72	71.72	85.68
Capacity Utilization (%)	%	100	121	72	86
Trend	Indexed	100.00	120.72	71.72	85.68

86. Data of domestic industry on capacity, production and capacity utilisation reveals that the capacity of the domestic industry was 40000 MT during 2003-04 and had not changed during POI. The production of subject goods was 40094 MT during 2003-04 after rising in 2004-05 to the level of 48403 MT declined to 28754 MT during 2005-06 and was 34275 MT during POI. The capacity utilisation of domestic industry, which was 121% during 2004-05, declined to 86% during POI, as compared to 100% in the base year 2003-04. The Authority notes that production in 2005-06 suffered because of longer shutdown taken by the Company due to difficulties in procurement of major raw material. However, the company had resumed full production in POI and could have produced to the extent of the volumes achieved in 2003-04 and 2004-05. During POI, while plant was ready to produce up to its installed capacity, it could operate only up to 86% of the capacity.

I.4.1 Sales volume of Domestic Industry

	Unit	2003-04	2004-05	2005-06	Annualized POI
Domestic Industry	Mt	37583	44265	28143	32548
Trend	Indexed	100.00	117.78	74.88	86.60

87. The data on sales indicates that the domestic industry sold 37583 MT of subject goods during 2003-04 which declined to 32548 MT during POI. The sale of domestic industry thus fell to 87% during POI as compared to base year 2003-04. The Authority notes that the domestic industry could sell 44265 MT during 2004-05 and sales during POI were significantly lower than these levels achieved earlier.

88. The above data on the sales of domestic industry shows that there was a fall in the sales during POI to the extent of 13% over the base year 2003-04 though sales during POI were higher than the sales achieved in 2005-06. As noted above, production during 2005-06 suffered on account of longer shutdown taken by the company, so did the sales. It is also noted that during the year 2004-05, domestic industry could sell 44265 MT as against 32548 MT during POI.

I.4.2 Demand and Market Share including captive Consumption

	Unit	2003-04	2004-05	2005-06	POI
Domestic Industry	Mt	37583	44265	28143	32548
Other Producers	Mt	35090	35410	28475	28289
Total Import	Mt	65425	65034	93441	91578
Total Demand	Mt	138098	144710	150059	152415
Trend	Indexed	100.00	104.79	108.66	110.36
Market share in demand					
Domestic Industry	%	27.21	30.59	18.75	21.35
Trend	Indexed	100.00	112.40	68.91	78.46
Other Producers	%	25.41	24.47	18.98	18.56
Trend	Indexed	100.00	96.30	74.68	73.04
Korea RP	%	0.00	0.02	4.68	6.41
Taiwan	%	0.00	1.37	16.49	16.35
USA	%	16.74	10.65	15.88	12.37
Subject Countries	%	16.74	12.04	37.05	35.13
Trend	Indexed	100.00	71.92	221.25	209.86
Import from Other countries	%	30.63	32.90	25.22	24.96
Trend	Indexed	100.00	107.40	82.34	81.49

I.4.3. Demand and Market Share excluding captive Consumption

	Unit	2003-04	2004-05	2005-06	POI
Domestic Industry	Mt	37583	44265	28143	32548
Other Producers	Mt	32329	34099	26952	26561
Total Import	Mt	65425	65034	93441	91578
Total Demand	Mt	135337	143399	148536	150687
Trend	Indexed	100.00	105.96	109.75	111.34
Market share in demand					
Domestic Industry	%	27.77	30.87	18.95	21.60
Trend	Indexed	100.00	111.16	68.23	77.78
Other Producers	%	23.89	23.78	18.14	17.63
Trend	Indexed	100.00	99.55	75.96	73.80
Korea RP	%	0.00	0.02	4.72	6.48
Taiwan	%	0.00	1.38	16.66	16.54
USA	%	17.09	10.75	16.04	12.51
Subject Countries	%	17.09	12.15	37.43	35.53
Trend	Indexed	100.00	71.13	219.05	207.90
Import from Other countries	%	31.26	33.20	25.48	25.24
Trend	Indexed	100.00	106.21	81.52	80.74

89. Imports from subject countries have increased significantly in relation to consumption India from 16.74% in 2003-04 to 35.13% in POI.

90. There has been a steady growth in demand of the subject goods. Over the base year 2003-04, the demand in POI was higher by 10%. The share of domestic industry which was at 27.21% in 2003-04 declined to 21.35% during POI. During the same period the share of imports from subject countries which was 16.74% in 2003-04 went up to 35.13% during POI. It is noted that dumped imports have not only captured the growth in demand but also crowded out the domestic industry.

91. The demand (excluding captive sales) of subject goods shows similar trend. It grew by 11% during POI as compared to the base year. The trend indicates that the share of domestic industry which was at 28% in 2003-04 declined to 22% during POI. During the same period the share of subject countries which was 17% in 2003-04 rose to 36% during POI.

1.5 Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

92. With regard to the effect of dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18, the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of like product in India or whether effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred to a significant degree.

93. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries have been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the weighted average cost of production, weighted average Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the Domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject countries.

1.5.1. Evaluation of price over period under consideration

Unit	Unit	2003-04	2004-05	2005-06	POI
Cost of sales	Rs./Mt	36851	48871	49093	50196
Trend	Indexed	100.00	132.62	133.22	136.21
Selling Price (NSR)	Rs./Mt	43249	63525	52175	53030
Trend	Indexed	100.00	146.88	120.64	122.62

1.6. Price undercutting and underselling effects

POI	Unit	Bulk	Packed	Total Weighted Average (Bulk + Packed)
Net sales realization	Rs./Mt	51925	57810	53030

Landed price				
Korea RP	Rs./Mt	47699	52980	48788
Taiwan	Rs./Mt	49672	65874	51437
USA	Rs./Mt	47441	74539	49487
Total subject countries	Rs./Mt	48513	67300	50267
Price undercutting				
Korea RP	Rs./Mt	4226	4830	4242
Taiwan	Rs./Mt	2253	-8064	1593
USA	Rs./Mt	4484	-16729	3543
Total subject countries	Rs./Mt	3412	-9490	2763
Price undercutting (%)				
Korea RP	%	8.14%	8.36%	8.00%
Taiwan	%	4.34%	-13.95%	3.00%
USA	%	8.64%	-28.94%	6.68%
Total subject countries	%	6.57%	-16.42%	5.21%
Non Injurious Price	Rs./Mt	56494	61873	57532
Price Underselling				
Korea RP	Rs./Mt	8795	8893	8798
Taiwan	Rs./Mt	6822	-4001	6130
USA	Rs./Mt	9053	-12666	8090
Total subject countries	Rs./Mt	7981	-5427	7307
Price Underselling (%)				
Korea RP	%	15.57%	14.37%	15.29%
Taiwan	%	12.08%	-6.47%	10.66%
USA	%	16.02%	-20.47%	14.06%
Total subject countries	%	14.13%	-8.77%	12.70%

I.6.1. Argument raised by interested parties

94. It has been argued by some interested parties that authority should disclose the price undercutting individually for each of such country. It has been further argued that Authority has not disclosed landed value of imports for previous years in the Preliminary Findings to enable them to compare the price trends of previous years.

I.6.2. Examination by the Authority.

95. Authority notes that the Rules do not require determination of price undercutting for the entire injury period. However, considering the argument, the Authority has determined price undercutting for the previous years as well as per details given below.

	Unit	2003-04	2004-05	2005-06	POI
Net Sales Realization	Rs./Mt	43249	63525	52175	53030
Trend	Indexed	100.00	146.88	120.64	122.62

Landed Price					
Korea RP	Rs./Mt		45537	51471	48788
Taiwan	Rs./Mt		84183	50760	51437
USA	Rs./Mt	38174	61824	54938	49487
Total subject countries	Rs./Mt	38174	64341	52641	50267
Price undercutting					
Korea RP	Rs./Mt	-	17988	704	4242
Taiwan	Rs./Mt	-	-20658	1415	1593
USA	Rs./Mt	5075	1701	-2763	3543
Total subject countries	Rs./Mt	5075	-816	-466	2763
Price undercutting (%)					
Korea RP	%	-	28.32%	1.35%	8.00%
Taiwan	%	-	-32.52%	2.71%	3.00%
USA	%	11.74%	2.68%	-5.30%	6.68%
Total subject countries	%	11.74%	-1.28%	-0.89%	5.21%

96. While working out the net sales realization of the domestic industry, the rebates, discounts and commissions offered by the domestic industry and the central excise duty paid have been rebated.

97. Price undercutting has been determined by comparing the weighted average landed value of dumped imports from the subject countries over the entire period of investigation with the weighted average net sales realization of the domestic industry for the same period. For this purpose landed value of imports has been calculated by adding 1% landing charge and applicable basic customs duty to the value reported in the DGCI&S data of import prices from the subject countries. The price undercutting from subject countries was in the range of 4-10% during POI.

98. For the purpose of price underselling the weighted average landed prices of imports from subject countries have been compared with the Non-injurious price of the domestic industry determined for the POI. It shows that underselling was in the range of 12-17%.

J. Post Disclosure submissions

J.1. Submissions made by Domestic Industry.

99. Domestic Industry has confirmed that all their contentions have been taken on record and appropriately brought out in the Disclosure statement. They have further requested that duties in terms of fixed amount, expressed in Indian Rupees be recommended as it would not be appropriate to recommend a benchmark price / variable duty, in view of the fact that raw material prices keep fluctuating continuously and violently. They have further sought determination of Non-Injurious-Price considering Gross Fixed Assets on the premise that basic plant and equipment are now fully depreciated and domestic and the methodology followed by the Authority implies that that Domestic Industry should earn no profits from production and sale of the product only because the relevant fixed assets are now fully depreciated.

J.2. Submissions made by other interested parties apart from the Domestic Industry.

100. The Authority notes that none of the producers of the subject goods in Korea-RP, Taiwan or USA has responded to the Designated Authority. However Laminate Manufacturers Association and M/S Century Ply Ltd., users of the subject goods have requested for termination of investigation raising following issues.

101. Laminate Manufacturers Association has made following submissions:

(i) The fact that the imports of subject goods by SI Group were substantial in volume ought to have been considered at the time of initiation of the present case and not at such later state. Withholding of such facts from the authority itself should be a good ground for termination of the present proceedings. In any case, such imports can not be included in the analysis under Annexure-II. The whole exercise therefore is vitiated.

(ii) We are unable to respond to contents of Para 17 as we had made no submissions on benchmark form of duty. Under Para 18, the Designated Authority sought to reject the submission of the Association without stating which submission is sought to be rejected. In view, thereof we are unable to respond or offer any further comments on these issues.

(iii) The issue of shutdown and its impact on injury to domestic industry was required to be examined and the same has not been appreciated in its true context. The authority has not been provided adjusted data for the purposes of proper injury analysis.

(iv) Preliminary findings were issued by the designated authority after having satisfied itself with regard to the need of the same. It is our respectful submission that the reasons of findings in support of such conclusion are not apparent from the record. As a quasi-judicial authority, the Designated authority was required to state such reasons in the preliminary findings. In the absence of such reasons for reaching such conclusions, the preliminary findings are bad in law. Similarly, we find numerous instances where the Designated Authority has recorded conclusions without recording reason for such conclusions.

(v) From the disclosure statement we find that Century Ply Ltd. responded and filed their written submissions. They have not been made available to us despite our request. Further, the correspondence exchanged with interested parties including domestic industry is also not available in public file. In the absence of such information, serious prejudice has been caused to the rights of interested parties to make effective comments to data and information for reaching determinations as contemplated under the Rules behind the back of the interested parties would clearly be contrary to law on natural justice.

(vi) We are unable to comment on that data relied upon by the authority as the same was not made available in the public file despite our request in our earlier submissions. The same we are sure, was not provided to the authority on confidential basis and could not

have been withheld as provisions of Rule 7 cannot be invoked by DGCI&S. The same is publicly available information and hence ought to have been provided to the interested parties.

(vii) The Designated Authority has indicated that**** in the disclosure statement represents information furnished by an interested party on confidential basis. However, there is nothing in the publicly available documents to show that the applicant had shown good cause to keep the said information confidential. In this connection, it was pointed out to the Authority right from the beginning of the investigations that the provisions of confidentiality have been abused and are being used contrary to the letter and spirit of law. There is no indication in any public document to even suggest that the Designated Authority had indeed applied his mind on the confidentiality aspect. It is a first time that in the disclosure statement it has been cursorily mentioned that the information supplied by the interested parties have been considered confidential by the designated authority. The exporters and other interested parties are in no position to comment whether the description of the designated authority has been used in accordance with the legal provisions and principles of natural justice.

(viii) Excessive confidentiality has been claimed and allowed in the present proceedings. It has further been alleged that the public file does not have any document on record to show that the confidentiality treatment has consciously been allowed by the authority and there no proper indexation on the public file.

(ix) Reliance on ICISLOR data relating to benzene prices and data relating to propylene prices, power costs, commissions, freight, marine insurance, bank charges, freight costs as having been kept confidential has been contested. It has also been stated that justification for use of raw material prices from ICISLOR data when the price of Phenol itself was available, has not been given.

(x) Reliance on findings in acetone case on BIFR status has been challenged and it has been suggested that HOCL be called upon to provide latest status on their case before BIFR. It has also been stated that since every information from HOCL can be obtained under RTI, no information should have been allowed to be kept as confidential.

(xi) Additional information obtained during proceedings in the form of deficiency letters and responses thereof has not been made available in the public file for comments/objections.

(xii) Data which has been worked out on various inputs relating to calculation of normal value particularly DGCI&S data and propylene prices from ICISLOR and other inputs from other sources have been sought to be made public.

(xiii) Final export price worked out based upon DGCI&S data after adjustments worked out for freight, marine insurance, commissions, inland freight, freight expenses, bank charges, and credit costs has been sought to be made public.

(xiv) Actual dumping margin have been sought to be disclosed in terms of figures and thereafter fresh comments should be sought from interested parties afresh. Actual calculations of working out of NIP in actual number has been sought to be disclosed.

(xv) Revised injury information stated to have been filed by the domestic industry have been sought to be disclosed and it has further been sought that after disclosing the same the interested parties should be given a proper opportunity for hearing as the one granted earlier was not effective as contemplated under law and principles of natural justice. It has been alleged that HOCL seeking 22% return on capital employed in spite of never having made any profits in last 10 years is indicative that survival of HOCL is only dependent on external supports either by way of safe guard duties or anti-dumping duty or by way of protection through tariffs. They have sought reasons as to why information for financial year 2002-03 in terms of DGAD trade notice no. 2/2004 dated 12.5.2004 have not been provided

(xvi) They have raised an issue as to whether DA had called for entire record of BIFR proceedings. They have alleged that soft copy of the import data used in the investigation have not been supplied to them.

(xvii) It has been alleged that the rejoinder submissions filed by all the parties have not made available to them. It has also been alleged that non confidential versions of all responses filed by the DI have not been made available to them.

(xviii) It has been stated that the some new facts have been introduced in the disclosure statement for the first time and interested parties were never put on notice.

(xix) It has been alleged that several parts of detailed submissions made by them have not been recorded in the disclosure statement. Interestingly, while the disclosure statement records in detail even the unsubstantiated submissions of the DI, the rebuttal and the arguments submitted by the Association and others are conspicuous by the absence.

(xx) The statements in the disclosure statement that all the information was available in the public file, is not borne out from the face of the record.

(xxi) Request for inspection of public file and for copies of the rejoinder statements has not been responded to till date. In any case there is no page numbering, index etc. in the public file. Such an approach is contrary to the guidance laid down by the Hon'ble CESTAT in earlier cases.

(xxii) The DA has not allowed request for a fresh hearing after the data has been revised. Fresh hearing was mandated as per principles of natural justice and administrative law. Balance of convenience also requires that the request as made may be allowed as no prejudice would be caused to the interest of DI if the prayer for grant of fresh hearing is allowed. However, if the same is not allowed, grave and irreparable harm and injury would be caused to the interest of the importers/exporters and user industry.

(xxiii) It has been wrongly stated that the "this investigation was initiated in accordance with the provisions of Rule 5". The Association had made detailed submissions pointing out the deficiencies and the incurable defects in the initiation procedure and the non-adherence to the requirements of Rule 5 in its written communications from time to time. Surprisingly, these have not been considered as "essential facts" by the Authority."

(xxiv) The statement that "adequate opportunity was given to submit information and make comments on the initiation and thereafter at every state of the investigations" is totally contrary to the facts of the case. In support we rely upon the above submissions. We also draw your kind attention to our submissions that DI actually withheld names of interested parties with whom they had regular dealing in Phenol.

(xxv) It is further incorrect to state in Para 44 that "...the Authority proposes to conclude that the performance of the Domestic industry deteriorated in terms of production.....thus cumulatively showing that the domestic industry has suffered material injury". It is pertinent to note that serious submissions made by the Association has escaped the attention of the Authority and has not even been made a part of the disclosure statement.

(xxvi) The views expressed by Association have been selectively reproduced in the disclosure statement. Most of the crucial aspects reflected in our communications have not even been recorded in the disclosure statement.

102. Fair Trade Practices on behalf of Century Ply has made following submissions:

i) The Designated authority in the disclosure statement has rejected the information furnished by the Century Ply in the form of Importer Questionnaire response as the same is according to the authority is not reflecting true position. It is submitted that even it is assumed that the information filed by the company suffers from some typographical errors the authority has not issued any deficiency letter any clarification. Therefore to out rightly reject the information which is otherwise reliable and supported by back-up papers at the end of the investigation without offering any opportunity to the importer is highly improper on the part of the designated authority.

ii) It is an admitted fact that the petition for imposition of anti-dumping was jointly filed by the HOCL and SI Group but the non-confidential version of the combined data filed by the petitioners has not been available to the other interested parties. It is submitted that the authority has itself noted in the preliminary findings as well as under disclosure statement that the petitioner were directed to injury information after excluding information pertaining to SI Group, but information initially filed was not shared with the interested parties despite repeated requests for the same. The information pertaining to SI Group filed by the petitioners have not been provided despite repeated requests for the same.

iii) The Designated Authority has also not segregated the volume of imports made by the SI Group from the total volume of imports from the subject countries which has further inflated the total volume of imports. It is submitted that one of the reasons for increase in the total volume of imports from the subject countries is significant importation of subject

goods by the SI Group from the subject countries as recorded by the authority in its findings as well and therefore for the purpose of injury analysis the imports made by Domestic producers/supporter of petition should have been excluded.

(iv) It is submitted that the publication of notification in the gazette is not an issue but the actual issue is intentional concealment of names of the actual users/importers of the subject goods by the petitioner in order to ward off any kind of opposition. The fact that petitioner despite knowing the names of the actual users choose not to give the same to the authority raises serious questions about the intention of the petitioner and vitiates the right of the interested parties to make effective participation.

(v) The long term shut down/suspension of production by the petitioner has been deliberately concealed by the petitioner. The mere reproduction of the same in the annual report does not absolve the liability/obligation of the petitioner to provide full fact in the petition for imposition of anti-dumping duty.

(vi) Injury information filed by the petitioner is also does not disclose this fact and on the contrary no information for the period of shut down period has been provided along with the financial data for the POI and three preceding years for the obvious reason to conceal the same and to present the injury information in the distorted way. Moreover the impact of shut down was nowhere analyzed either by petitioner or by the authority in the petition or in the preliminary findings/disclosure statement. The same was concealed by the petitioner can also be seen from the final findings of the mid term review, where the same was conspicuously missing.

(vii) On the issue of injury we once again reiterate our submission filed earlier during the course of investigation, which is as under:

(viii) The petitioner has deliberately filed petition targeting period of investigation, which is already marred by deliberate shut down of the plant by the HOCL. The petitioner in an endeavor to stage injury to the DI has chosen period just after the period of its shutdown. The domestic Industry first shut down its plant for a very long period on a flimsy reason that the raw material was not available thereby putting already short supply market in to dire situation leaving all the users in lurch. The scarcity of phenol in the Indian market leads to import of goods from subject countries. It should be noted that all the economic indices prior to shut down were showing positive growth and the domestic industry was running in the pink. Shut down for the period of Apr. 05-June 05 has affected the performance of the domestic industry. Further SI has imported subject goods for its own captive consumption. Imports by SI should be excluded while determining effect of volume of imports.

(ix) The domestic industry has been able to increase its selling price. The price undercutting is 5-10% only, as determined by the Authority. We request the Authority to disclose the price undercutting individually for each of the subject country. Further the landed value of imports for the previous years has not been disclosed in the preliminary findings to enable us to compare the price trend of the previous years.

(x) Further it is submitted that they hypothetical assumption taken by the authority in the relation of injury analysis keeping in view the shut down period is far away from the reality.

(xi) The disclosed statement states that:

“Domestic industry had faced plant shutdown in 2005-06. Domestic industry assuming it would have produced at the same rate during the shutdown period as it had produced in 2005-06 and sold all such production, has provided a detailed analysis, which is tabulated below:”

Assuming that there was no shut down, the domestic industry would have performed as it had performed during 2004-05. Moreover, it is unacceptable that the effect of shut down would have been limited to the period of shut down only as abrupt stoppage of complete supply from the domestic industry has forced the users to look outwards and enter long term supply contract to ensure uninterrupted supply of subject goods to keep their production facilities running. It is submitted that the share of DI has fallen due to static production capacity and long term shut down. It is submitted that the demand for the subject goods has been increasing rapidly but the domestic industry or other Indian producer have not been adding capacities for meeting the same.

(xii) It is submitted that given the huge demand supply gap between the total demand in India and production capacity in Indian there is constant need for importation of subject goods from countries out side India. The capacities of the DI over the years have remain static as no expansions have been carried out by any of the producers in India but on the contrary the same has further declined due to non-production of subject goods by the Neyveli Lignite and abrupt long term suspension of subject goods by the petitioner company HOCL.

(xiii) The purpose of the imposition of anti-dumping duty is to provide a fair price level to the DI rather than to impose penalty upon the actual user/imports of the subject goods or to impose blanket ban upon the imports by making them unviable by imposing arbitrarily high rate of duty irrespective of the facts that the subject goods are coming an un-dumped prices. The export prices from the subject countries have increased significantly during post period of investigation.

J.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

103. The Authority has examined the submissions made by the users as above and concludes that the issues raised are not supported by facts and figures.
104. Exclusion of SI group has already been dealt with in the initiation notification and the Preliminary Findings and need not be repeated a fresh.

105. The plant shut down and its impact has been properly examined and detailed in the Preliminary Findings.
106. It has been alleged that the Authority has recorded conclusions without recording reason of such conclusions. However no specific mention of these stated numerous instances has been pointed out.
107. DGCIS data being publicly available as brought out in the submissions, there is no reason for the association to plead on this aspect as they were at liberty to procure the same from Public Domain.
108. It has not been specifically mentioned as to on which information has confidentiality been claimed which is available in public domain.
109. Costing information and other business sensitive information which has been allowed to remain confidential cannot be obtained under RTI.
110. Similarly ICISLOR data is a paid data and the users have the freedom to have access to the same.
111. To sum up the issues have been raised merely for the sake of raising an issue and are not substantiated. The confidentiality issue has been raised in a big way without reliance upon the facts. The mere fact that the consumer Industry woke up only once the preliminary findings were issued goes in a big way to support the decision of the Authority in relying on facts and figures available for concluding Findings. Even at this stage, including the stage of Oral hearing, pre-disclosure and post disclosure stages, the user industry has sought to raise issues in the form of a text without providing any data which could help the Authority determine dumping and injury margins. The user Industry was at liberty to have access to documents / data claimed to be available in public domain and therefore accusing the authority of giving confidential status to such data is misplaced. Denying access to public file, not maintaining it properly and not providing post hearing submissions to the users is denied. The Authority does not deem it necessary to respond to vague and uncalled for allegations, primarily because of the lack of proper response from the user industry and because whatever response is there is only in the form of vague submissions, those too when the investigations are nearing completion. The Authority is of the view that the submissions made by these users are only an alibi to delay the investigations and draw a mileage of having participated in the proceedings. The mere fact that Century Ply is a part of the Laminate Manufacturers Association and association accusing the authority of not having made available the submissions made by Century ply is a clear indicator of this conclusion. To sum up, the Authority concludes that the submissions made by the association are nothing but a delaying tactics.

K.1. Price suppression and depression effects of the dumped imports:

112. The price suppression effect of the dumped imports has also been examined with reference to the cost of production, net sales realization and the landed values from the subject countries.
113. The Authority notes that there were upward trends in the cost of sales during the injury period. The cost of sales which was 100 (indexed) in the base year went up to 136.21 in the POI; mainly due to increase in input price of Benzene and LPG which are

Petro based products. The Authority notes that though the increase in the selling price was more than the cost up to 2004-05, thereafter the increase in selling price was not proportionate to the increase in cost. The trend of cost of production shows that weighted average cost of production rose by 36% during POI as compared to base year whereas the selling price had increased only by 23% during POI indicating that the domestic industry could not realize the selling price commensurate with the increase in cost of production.

K.2. Examination of other Injury Parameters

114. After having examined the effect of dumped imports on the volumes and prices of the domestic industry and major injury indicators like volume and value of imports, capacity, output, capacity utilization and sales of the domestic industry as well as demand pattern with market shares of various segments in the earlier section, other economic parameters which could indicate existence of injury to the domestic industry have been analyzed hereunder as follows:

K.3. Profits and actual and potential effects on the cash flow

	Unit	2003-04	2004-05	2005-06	POI
Cost of sales	Rs./Mt	36851	48871	49093	50196
Trend	Indexed	100.00	132.62	133.22	136.21
Selling Price (NSR)	Rs./Mt	43249	63525	52175	53030
Trend	Indexed	100.00	146.88	120.64	122.62
Profit/Loss	Rs./Mt	6398	14654	3082	2834
Trend	Indexed	100.00	229.04	48.18	44.29
Profit/Loss before Tax	Rs./Lacs	2404.53	6486.50	867.50	922.25
Trend	Indexed	100.00	269.76	36.08	38.35
PBIT	Rs./Lacs	2647.86	6691.97	1036.49	1095.25
Trend	Indexed	100.00	252.73	39.14	41.36
Cash Profit	Rs./Lacs	2521.03	6594.21	939.28	995.61
Trend	Indexed	100.00	261.57	37.26	39.49

115. The data indicate that weighted average cost of production of the domestic industry went up by 36% during POI as compared to base year against which the weighted average selling price increased only by 23% during POI. The profit per unit which was 100 (indexed) in the base year increased by 129% during 2004-05 and declined in 2005-06 to 48% and 44% during POI. The profit of domestic industry on the domestic sales(PBIT) which was 100 (indexed) in 2003-04 increased by 154% in 2004-05 and declined in 2005-06 to 39% and 41% during POI. The Authority notes that there has been significant deterioration in the profitability of domestic industry during the POI as compared to base year 2003-04.

K.4 Return on investment and ability to raise capital

	Unit	2003-04	2004-05	2005-06	POI
PBIT	Rs./Lacs	2647.86	6691.97	1036.49	1095.25
Trend	Indexed	100.00	252.73	39.14	41.36
Net Fixed Assets	Rs./Lacs	1476.06	1372.65	1077.23	1132.05
Trend	Indexed	100.00	92.99	72.98	76.69
Working Capital	Rs./Lacs	2832.98	4289.04	3444.61	4008.66
Trend	Indexed	100.00	151.40	121.59	141.50

Capital Employed - NFA	Rs./Lacs	4309.04	5661.69	4521.84	5140.71
Trend	Indexed	100.00	131.39	104.94	119.30
Return on Capital Employed (NFA Basis)	%	61.45	118.20	22.92	21.31
Trend	Indexed	100.00	192.35	37.30	34.67

116. The Authority notes that there has been continued decline in the % age return on capital employed earned by the domestic industry. The return on capital employed, which was 100 (indexed) in the year 2003-04 declined sharply to 34.67 in POI.

K.5. Productivity

	Unit	2003-04	2004-05	2005-06	POI
Productivity per employee	Mt	207 lamine Manufactur ers Association and M /S century Ply Ltd..49	247.91	153.53	180.39
Trend	Indexed	100.00	119.48	73.99	86.94

117. The data on production per employee shows that the productivity increased by 119% in 2004-05 before declining to 87% during POI as compared to base year.

K.6. Employment and wages

	Unit	2003-04	2004-05	2005-06	POI
Employment (Manpower strength)	Nos.	193	195	187	190
Trend	Indexed	100.00	101.04	96.93	98.33
Wages	Rs./Lacs	140.16	163.78	168.87	173.93
Trend	Indexed	100.00	116.86	120.49	124.10

118. The employment level does not show significant change. In indexed form it declined to 98% during POI as compared to base year. The wages increased by 24% during POI as compared to base year.

K.7 Inventories

	Unit	2003-04	2004-05	2005-06	POI
Opening Stock	Mt	688	2924	2214	207
Closing Stock	Mt	2924	2214	2618	1728
Average Stock	Mt	1806	2569	2416	967
Trend	Indexed	100.00	142.25	133.76	53.55
Average Stock in terms of No. of Days' sales	Nos.	18	21	31	11
Trend	Indexed	100.00	120.77	178.63	61.83

119. The trends in the average inventory show that average inventory declined from 100 in the base year to 54 during POI. The Authority notes that at the beginning of POI the opening inventory was equal to about 2 days sales, which went up to about 19 days sales at the close of POI. In other words, during POI there has been accumulation of inventory as the closing inventory was nearly 8 times the opening inventory, which reflects an adverse off take.

K.8. Growth

120. The growth in demand shows positive trend from base year to POI on year to year basis. The growth in production and sales were positive in 2004-05, negative in 2005-06 and again positive during the POI. The cost of production shows rising trend in 2004-05, 2005-06 and in POI. Growth of selling price shows rising trend in 2004-05 and negative in 2005-06 and positive in POI. Growth of profits shows positive trend in 2004-05 and negative in 2005-06 and positive in POI.

K.9. Investment and Ability to raise capital Investment

121. The authority notes that the domestic industry had not changed the capacity of subject goods from base year to POI. There has been no fresh investment by the domestic industry during the period of investigation and there is no plan for further investment as submitted by them.

K.10. Magnitude of Dumping

122. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry shows that the dumping margins determined against the subject countries, for the POI, are significant.

K.11. Factors affecting prices

123. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred to a significant degree. In order to assess the effect of imports on the domestic market, the Designated Authority analyzed import prices over the injury period. It was found that the landed value per MT in POI was lower than both the net selling price and non-injurious price of bulk phenol in respect of all subject countries. It was also found that the landed value of import per MT in the POI is higher than the net selling price and the non-injurious price in respect of packed phenol from all subject countries excepting Korea RP. Out of total imports from subject countries during POI, the packed and bulk imports are 5% and 95% respectively. Change in cost structure if any, due to competition in the domestic industry and prices of competing substitutes have been examined for analyzing the factors that might be affecting the prices in the domestic market. The weighted average cost of production has increased by 36% during POI. The weighted average net selling prices increased only by 23% during the same period. The Authority notes that Landed values of imported material from subject countries are significantly below the selling price of the domestic industry, causing price undercutting in the Indian market. The undercutting during POI was in the range of 4-10% and underselling was in the range of 12-17% during POI.

K.12. Conclusion on injury

124. The examination of above injury parameters indicates that growth in demand was 10% (including captive sales) during POI as compared to base year. Despite overall growth in demand, both the production and sale of domestic industry declined to 85% and 87% respectively during POI as compared to base year 2003-04. During the same period, the imports of subject goods from subject countries increased significantly from 23123 MT in 2003-04 to 53538 MT during POI i.e. it increased by 132%. The share of the imports from subject countries in relation to demand increased from 17% in 2003-04 to 35% during POI whereas the share in demand of the domestic industry declined from 27% to 21% during the same period. The Authority notes that imports have crowded out domestic industry in domestic market. The capacity utilization of the domestic industry, despite growth in demand, declined from 100% to 86% during POI. Thus the installed capacity remained unutilized during POI. Profits (PBIT) declined to 41 during POI as compared to base of 100. The return on net capital employed declined to 21 during POI as compared to 100 of base year 2003-04.

125. Imports from subject countries have increased significantly and these had significant adverse price effect resulting in price suppression and price undercutting.

126. It was argued by interested parties that the domestic industry had faced plant shutdown in 2005-06. Domestic Industry, assuming it would have produced at the same rate during the shutdown period as it had produced in 2005-06 and sold all such production has provided a detailed analysis and the same is elaborated below.

	Unit	2003-04	2004-05	2005-06 adjusted	POI
Installed Capacity	Mt	40000	40000	40000	40000
Trend	Indexed	100	100	100	100
Production	Mt	40094	48403	34348	34275
Trend	Indexed	100	121	86	85
Capacity Utilization (%)	%	100.24	121.01	85.87	85.69
Trend	Indexed	100	121	86	85
Domestic Sales	Mt	37583	44265	33737	32548
Trend	Indexed	100	118	90	87
Cost of production	Rs./Mt	36851	48871	48421	50196
Trend	Indexed	100.00	132.62	131.40	136.21
Selling Price	Rs./Mt	43249	63525	52175	53030
Trend	Indexed	100	147	121	123
Profit/Loss	Rs./Mt	6398	14654	3754	2834
Trend	Indexed	100	229	59	44
Profit/Loss	Rs./Lacs	2404.53	6486.50	1266.49	922.25
Trend	Indexed	100	270	53	38
PBIT	Rs./Lacs	2647.86	6691.97	1435.48	1095.25
Trend	Indexed	100	253	54	41
Cash profit	Rs./Lacs	2521.03	6594.21	1338.28	995.61
Trend	Indexed	100	262	53	39

ROCE	%	61.45	118.20	31.75	21.31
Trend	Indexed	100	192	52	35
Productivity per employee	Mt	207	248	183	180
Trend	Indexed	100	119	88	87
Import from subject countries	Mt	23123	17427	49997	53538
Trend	Indexed	100	75	216	232
Import from other countries	Mt	42302	47607	37850	38040
Trend	Indexed	100	113	89	90
Total Import	Mt	65425	65034	87847	91578
Trend	Indexed	100	99	134	140
Sales of domestic industry	Mt	37583	44265	33737	32548
Sales of other producers	Mt	35090	35410	28475	28289
Total demand	Mt	138098	144710	150059	152415
Trend	Indexed	100	105	109	110
Market share in demand					
Domestic industry	%	27.21	30.59	22.48	21.35
Other producers	%	25.41	24.47	18.98	18.56
Subject countries	%	16.74	12.04	33.32	35.13
Other countries	%	30.63	32.90	25.22	24.96

127. On the basis of above analysis, the Authority concludes that the performance of the domestic industry deteriorated in terms of production, sales volumes, capacity utilization, market share, factors effecting prices, profits, return on investment, cash profits, thus collectively and cumulatively showing that the domestic industry has suffered material injury.

K.13. Causal Link

128. In order to reach its conclusions on the cause of the injury suffered by domestic industry and in accordance with article 3.5 of Agreement on Anti-Dumping and as per Para (v) of Annexure-II under Rule 11 under Customs Tariff Act as amended, the Authority examined the impact of all known factors and their consequences on the situation of the domestic industry. Known factors other than dumped imports, which could at the same time have injured the domestic industry, were also examined to ensure that the possible injury caused by these other factors was not attributed to the dumped imports. The significant increase in volume of dumped imports from the subject countries (both in absolute terms as well as in relation to the share in demand) has resulted in significant decline in market share of the domestic industry. Decline in market share of domestic industry as a consequence of increase in market share of subject countries prevented the domestic industry from increasing their sales commensurate to increase in demand in the market. On the contrary, there was a decline, both in production and sale during POI as compared to base year 2003-04. As a result, domestic industry could not optimally utilize its capacity as capacity utilization during POI was only 86%. Consequently growth in production, sales and capacity utilization of the domestic industry suffered as a result of the decline in market share of domestic industry.

129. Significant price undercutting caused by imports prevented the domestic industry from increasing its prices to the extent of increase in costs. Consequently, profits, cash flow and return on investment deteriorated during POI after showing consistent improvement. While domestic industry was able to increase prices in 2003-04 and 2004-05, its performance deteriorated in the POI due to dumped imports which prevented it from effecting legitimate price increases.

130. It is thus concluded that the imports from the subject countries have caused material injury to the domestic industry.

L. Examination of Other Known Factors

L.1. Volume and prices of imports from other sources

131. The Authority notes that out of total imports, the volumes of imports from other countries are 42% during POI. The Authority notes that the imports from other countries also have been contributing to the injury of the domestic industry. It has been noted that the imports from other countries are already attracting anti-dumping duties.

L.2. Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

132. The Authority notes that there is no contraction in the overall demand during POI. On the contrary; overall demand for subject goods has shown positive growth during the injury period. The total demands of subject goods have shown growth of 10% (including captive sales) during Period of Investigation as compared to the base year. There is also no significant change in consumption pattern of the product in the domestic market, which could be attributed to the injury to the domestic industry.

L.3. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

133. The Authority notes that there is a single market for the subject goods where dumped imports from subject countries compete directly with the subject goods produced by domestic industry. The Authority also notes that the imported product is sold to meet the similar commercial grades and specifications as domestically produced subject goods and that the imported subject goods and domestically produced goods are like articles and are used for similar applications/ end uses.

134. The Authority notes that there is no restricted practice prevalent in the industry which could be attributed to the injury to the domestic industry.

L.4. Development of technology

135. On the basis of examination of the records of the petitioner, the Authority proposes to hold that development in technology has not been a relevant factor for the injury to the domestic industry.

L.5. Export performance

136. The Authority notes that the export volume of the domestic industry is insignificant during the POI. The performance with respect to various Economic indicators have determined with respect to domestic sales only. Hence, the Authority

proposes to hold that material injury suffered by the domestic industry may not be as a result of the export performance of the domestic industry.

L.6. Productivity of the Domestic Industry

137. Productivity of the domestic industry in terms of production per employee has shown decline during POI as compared to base year 2003-04 because of the decline in total production during the same period.

138. No other factor which could have possibly caused injury to the domestic industry has been brought to the knowledge of Authority.

M. Conclusion On Causation

139. Significant increase in the volume of dumped imports has resulted in significant decline in the market share of domestic industry. It is further seen that decline in market share of domestic industry as a consequence of increase in market share of subject imports from subject countries prevented the domestic industry from increasing their sales commensurate to growth in demand. As a result, sales of domestic industry during POI did not increase to such an extent that domestic industry could have optimally utilized its capacity. Consequently, production, sales and capacity utilization of the domestic industry suffered as a result of the decline in the market share of the domestic industry. Significant price undercutting caused by dumped imports prevented the domestic industry from increasing its prices to the extent of increase in costs. Resultantly, profit, cash flow and return on investment of the domestic industry deteriorated in the POI. Significant price-undercutting and substantial increase in the volume of dumped imports adversely affected the performance of the domestic industry in terms of profits, cash flow, and return on investment, which parameters deteriorated in POI after improving till 2004-05.

140. The Authority has therefore, concludes that the dumped imports originating in the subject countries have caused material injury to the domestic industry within the meaning of Rule 11 of Anti-dumping Rules and article 3.5 of Agreement of Anti-dumping.

N. Magnitude of Injury and injury margin

141. The non-injurious price determined by the Authority has been compared with the landed value of imports for determination of injury margin. The weighted average landed price of imports from each of the subject country and the injury margins have been determined as follows:

Name of company	USD/MT			
	Injury Margin (Bulk)	Injury Margin (Packed)	Injury Margin (Weighted Average)	Injury Margin (%)
Exporters from Korea-RP	196	198	196	15.29%
Exporters from Taiwan	152	-89	137	10.66%
Exporters from USA	202	-283	181	14.06%

O. Conclusions

142. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority, as recorded in this finding, the Authority concludes that:

- i) The subject goods have entered the Indian market from the subject countries at prices less than their normal values in the domestic markets of the exporting countries, resulting in dumping of the product in the Indian market;
- ii) The dumping margins of the subject goods imported from the subject countries are substantial and above de minimis;
- iii) The domestic industry has suffered material injury; and
- iv) the injury has been caused to the domestic industry, both in terms of volume and price effect by the dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

P. Indian industry's interest & other issues

143. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

Q. Recommendations

144. Having initiated and conducted investigation into dumping, injury and causal links between dumping and injury to the domestic industry in terms of the Rules laid down and having established positive dumping margin against the subject countries, as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive duty is required to offset dumping and injury to the domestic industry. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder.

145 Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends that definitive anti dumping duties be imposed on all imports of the subject goods falling under chapter 27 and 29 of Custom Tariff Classification Act 1975, originating in or exported from USA, Korea-RP and Taiwan to be collected from the date of imposition of the provisional duty. The anti-dumping duty shall be the amount mentioned in Column No. 8 of the following table.

Duty Table

S.No.	Sub Heading Of Tariff item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit Measure	Currency
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2907.1110 OR 2707.9900	PHENOL	USA	Any	Any	Any	181	MT.	USD
2.	DO	DO	Any other than Korea RP and Taiwan	USA	Any	Any	181	MT	USD
3	DO	DO	Taiwan	Any	Any	Any	137	MT	USD
4.	DO	DO	Any other than USA and Korea RP	Taiwan	Any	Any	137	MT	USD
5.	DO	DO	Korea RP.	Any	Any	Any	196	MT	USD
6.	DO	DO	Any other than Taiwan and USA	Korea RP	Any	Any	196	MT	USD

146. Subject to the above the provisional findings, notified vide notification dated 29th August 2007, are hereby confirmed

R. Further Procedures

147. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

148. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party as per the time limit stipulated for this purpose.

R. GOPALAN, Designated Authority